



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]
No. 434]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 19, 2007/चैत्र 29, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2007/CHAITRA 29, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2007

सं. 1 (आरई-2007)/2004-2009

का.आ. 607(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 19 अप्रैल, 2007 तक यथा अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा निहित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 को एतद्वारा अधिसूचित करती है। यह नीति 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/विदेश व्यापार नीति/एएम 08/पीसी-1]

भवानी सिंह मीना, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

विदेश व्यापार नीति

प्रस्तावना

सन्दर्भ

विश्व व्यापार में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देश के विदेश व्यापार के समग्र विकास हेतु विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि का विशेष महत्व है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को उद्वेलित करने के लिए हमें जरूरी आयातों को सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। विकास के लिए इन नीतियों के योगदान को अधिकतम करने हेतु व्यापार और अन्य आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य और सुसंगति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वार्षिक निर्यात-आयात नीति घोषित करने की मौजूदा परम्परा को जारी रखते हुए इससे कहीं आगे जाकर भारत की विदेश नीति की विकासात्मक आवश्यकताओं का समेकित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नयी विदेश व्यापार नीति इसी सन्दर्भ में जारी की जा रही है।

उद्देश्य

व्यापार अपने आप में अन्तिम उद्देश्य नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का माध्यम है। प्रमुख उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं बल्कि संबंधित आर्थिक कार्यकलापों को उद्वेलित करना है। विदेश व्यापार नीति इस विचारधारा से प्रेरित है और दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रभावित है, जोकि इस प्रकार है:-

1. अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हमारी भागीदारी की प्रतिशतता को आगामी पांच वर्षों के भीतर दो गुनी करना; तथा
2. रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास के प्रभावी उपकरण के तौर पर कार्य करना।

रणनीति

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है:

1. हमारे व्यवसायकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों की स्वाभाविक उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाने हेतु नियंत्रणों को हटाना।
2. प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सौदे की लागत को कम करना।
3. इस मूल सिद्धान्त के आधार पर कि शुल्कों और प्रशुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, अतः निर्यात उत्पादों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों पर सभी प्रशुल्कों और शुल्कों को निष्प्रभावी बनाना।

4. विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में भारत को एक विश्व ताकत के रूप में विकसित करना।
5. उन क्षेत्रों का पता लगाना तथा इन्हें विकसित करना जिनपर विशेष बल दिया जाना है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रेरक स्रोतों को विकसित करना।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों का आयात करके, इस प्रकार गुणवत्ता के स्वीकृत मानदण्डों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्राप्त करते हुए मूल्य संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
7. शुल्क वापसी के ढांचे की प्रणाली से बचना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे घरेलू क्षेत्र निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए मुक्त व्यापार समझौतों/क्षेत्रीय व्यापार समझौतों/प्राथमिक व्यापार समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
8. अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सम्पूर्ण विदेशी व्यापार शृंखला से संबंधित वास्तविक और आभासी दोनों के बुनियादी नेटवर्क को विकसित करना।
9. व्यापार बोर्ड की भूमिका को पुनः परिभाषित करके इसे पुनः जीवित करना, इसे उचित मान्यता देना तथा व्यापार नीति में विशेषज्ञों को शामिल करना।
10. हमारी निर्यात रणनीति में हमारे दूतावासों की मुख्य भूमिका निभाने के लिए गतिशील बनाना और विदेश में हमारे वाणिज्यिक प्रभागों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म से जोड़ना ताकि वास्तविक रूप से व्यापार आसूचना और पूछताछ के दायरे को बढ़ाया जा सके।

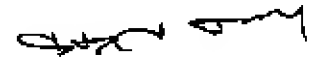
भागीदारी

नई नीति में कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक/व्यापारिक निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक, व्यापार और उद्योग जगत सरकार के भागीदार हैं। लम्बे समय तक चलने वाली और अनावश्यक मुकदमेबाजी भागीदारी को बिगाड़ती है। मुकदमेबाजी की जरूरत को दूर करने के लिए सृजनात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, जो मुकदमेबाजी को काफी कम करेगी और भागीदारी के रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

उदार व्यापार प्रणाली का गति विज्ञान कई बार डम्पिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाता है। जब ऐसा घटित होता है तो इस नुकसान को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

प्रारूप (रोड मैप)

यह नीति भारत के विदेश व्यापार के विकास हेतु अनिवार्य प्रारूप है। हमें जिस दिशा में अग्रसर होना है उसके आधार भूत सिद्धांत और मुद्दे इसमें शामिल हैं। कोई व्यापार नीति केवल अपने गति-विज्ञान की वजह से ही अपने सभी ब्यौरों के बावजूद पूर्णतः व्यापक नहीं हो सकती है। इसके लिए समय समय पर संशोधन करना स्वाभाविक तौर पर आवश्यक होगा। हम अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अवश्यंभावी परिवर्तनशील गति-विज्ञान पर आधारित निरन्तर अद्यतन करने के माध्यम से ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं। व्यापार और उद्योग जगत के साथ भागीदारी के माध्यम से हम इस प्रारूप (रोड मैप) पर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।



(कमल नाथ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली

31 अगस्त, 2004

शब्दावली**संक्षिप्त अक्षर****पूर्णक्षर**

एसीसी	सीमाशुल्क उपायुक्त
एसीयू	एशियायी निकासी संघ
एईजैड	कृषीय निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और विसीय पुनर्स्थापना बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार निगम
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव तकनीकी पार्क
सीबीईसी	उत्पाद सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीआईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीआईएफ	लागत बीमा और भाड़ा
सीआईएस	स्वतन्त्र राज्य का कॉमनवेल्थ
सीओडी	नकद भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीवीडी	कार्कंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीओबीटी	जैव तकनीकी विभाग
डीसी	विकास आयुक्त
डीईपीबी	शुल्क पात्रता पासबुक योजना
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओई	विद्युत विभाग
डीओआईटी	सूचना तकनीकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा

ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएच	निर्यात सदन
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण समिति
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातानुमुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआईआईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफएमएस	फोक्स बाजार योजना
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीएस	फोकस उत्पाद योजना
एफटी (डी एंड आर)	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 20)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य संधि
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
एचएसीसीपी	खतरा विश्लेषण और नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी वी1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)
एचबीपी वी2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड संख्या (कूट)
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (तालमेल प्रणाली) निर्यात और आयात मर्चों का वर्गीकरण, 2004-2009
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
एलओसी	साख पत्र
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक शपथ-पत्र
एमएआई	बाजार पहुँच अभिप्रेरण
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश व्यापार मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय

एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीआरसी	नीति छूट समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
पीटीएच	प्रीमियर व्यापार सदन
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएससीक्यू सी	गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप समिति
एसबी	घात लदान बिल
एसईएच	स्टार निर्यात सदन
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टिट्यूट कंपाबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	भारत से सेवित योजना
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईओएन	मानक निवेश उत्पादन मानदंड
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपी	सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क
टीईई	टाऊनस ऑफ एक्पोर्ट एक्सेलेस
टीएच	व्यापार सदन
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
वीए	मूल्य संवर्धन
वीआरजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
डब्ल्यू एचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्माण

अध्याय - एक (क)**विधिक ढाँचा**

प्रस्तावना	1.1	प्रस्तावना में वृहत ढाँचे को इंगित किया गया है तथा यह विदेश व्यापार नीति का अभिन्न अंग है।
अवधि	1.2	यह विदेश व्यापार नीति जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है 1 अप्रैल, 2007 से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए।
संशोधन	1.3	केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में अधिसूचना द्वारा संशोधन का अधिकार रखती है।
	1.4	इस नीति से पूर्व जारी किए गए प्राधिकार पत्र उस उद्देश्य और अवधि के लिए जिसके लिए ये प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
अन्तर्वर्ती व्यवस्था	1.5	यदि इस विदेश नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध से पूर्व स्थापित अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्रति ऐसे निर्यात या आयात का पोट तदान उपलब्ध बकाया और समय अविध के संबंध में ऐसे प्रतिबंध से लागू होने की मूल वैधता अवधि के भीतर हो जाए। तथापि, ऐसे साख-पत्रों के परिचायन की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

अध्याय - एक (ख)**विशेष ध्यान देने योग्य पहल**

विशेष फोकस
पहल

- 1ख.1 विश्व व्यापार में 5 वर्ष के अन्दर अपनी भागीदारी का प्रतिशत दुगुना करने तथा विशेष रूप से अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण तथा चमड़े से बने सामान के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाने कुछ विशेष फोकस पहल की पहचान कर ली गयी है।

भारत सरकार इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिनके लिए क्षेत्र विशेष रणनीति तय करेगी जिसको समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

घोषित की जाने
वाली नई क्षेत्रीय पहल

समय-समय पर अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पहलों की घोषणा की जाएगी

इन विशेष क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी :-

(1) कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र

- (क) विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना
- (ख) कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जैड) के विकास के लिए ए एस आई डी ई के अन्तर्गत धन निर्धारित किया जाएगा।
- (ग) हटा दिया गया है।
- (घ) हटा दिया गया है।
- (ङ) ई पी सी जी के अन्तर्गत पूंजीगत माल ए ई जैड में किसी भी स्थान पर स्थापित करने की अनुमति होगी।
- (च) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैनल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अनुमति होगी।
- (छ) कृषि निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकारण पत्र के तहत कीटनाशकों जैसे निवेशों के आयात की अनुमति होगी।

- (ज) ₹ 250 करोड़ की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात श्रेष्ठता प्राप्त नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) हथकरघा

- (क) हथकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एम.ए.आई./ एम डी ए योजना के तहत विशिष्ट निधि निर्धारित की जाएगी।
- (ख) विशिष्ट कतरनों और अलकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।
- (ग) हाथ से बुनी हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगा।
- (घ) हाथ से बुने हुए कालीनों के पुराने टुकड़ों की खेप का शुल्क मुक्त आयात का पुनः निर्यात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।
- (ङ.) ₹ 250 करोड़ की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात श्रेष्ठता प्राप्त नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।
- (च) हथकरघा निशान हथकरघा उत्पादों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ विशेष बाजार विकसित करता है।
- (छ) जल शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे।

(iii) हस्तशिल्प

- (क) नये हस्तशिल्प एस ई जैड स्थापित किए जायेंगे जो निर्यात के लिए कुटीर क्षेत्र से खरीदे गए उत्पाद को तैयार करेंगे।
- (ख) कटाई और छटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत

पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत होगी। हकदारी विस्तार प्राप्त है जिसकी सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

- (ग) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जो परोक्ष रूप से निर्यात करने में सुदृढ़ नहीं हैं के कतरनों, अलंकरणों और उपभोज्यों को आयात करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) हस्तशिल्प के प्रोत्साहन हेतु एमएआई/एमडीए योजनाओं के अधीन विशिष्ट निधियाँ निर्धारित की जाएंगी।
- (ङ) कतरनों अलंकरणों और उपभोज्यों के शुल्क मुक्त आयात पर सी वी डी में छूट प्राप्त होगी।
- (च) ₹ 250 करोड़ की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात श्रेष्ठता प्राप्त नये कंस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।
- (छ) जल शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे।

(iv) रत्न और आभूषण :

- (क) 8 कैरेट और अधिक के स्वर्ण का आयात प्रतिभूति योजना के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु मात्रा दर्शाता हुआ एक ऐसा प्रमाण पत्र भी हो।
- (ख) स्वर्ण प्लेटिनम के अलावा धातुओं के लिए उपभोज्यों उपकरणों, मशीनरी और उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी तथा स्वर्ण और प्लेटिनम हेतु विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 1% होगी तथापि, रेडियम जड़ित चांदी के आभूषणों हेतु हकदारी 3% होगी।
- (ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त निर्यात हकदारी 300,000 रुपये होगी।

(घ) अस्वीकृत दिए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी।

(ङ.) रत्न और आभूषणों की कटाई एवं पोलिश आयकर अधिनियम के खण्ड-10 क के अधीन छूट के उद्देश्य के लिए तैयार माल की तरह माना जायेगा।

(v) चमड़ा और जूते

(क) विनिर्दिष्ट मर्दों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।

(ख) जूतों (चमड़ा और सिंथेटिक दोनों) दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए कतरनों अलंकरणों और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी। ऐसी हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे हुए जूतों के डिब्बे, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

(ग) जलशोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण को मूल सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(घ) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खालें एवं चमड़ा और नम नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमत है।

(ङ.) अस्तर और अन्तः अस्तर सामग्री सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01-03-2003 की क्रम सं. 168 के अंतर्गत सी वी डी से छूट प्राप्त है।

(च) आई टी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन आने वाले कच्चा, टॉन किए गए और ड्रेस लोम खालों पर सीवीडी से छूट प्राप्त होगी।

समुद्री क्षेत्र के लिए पैकेज

(vi)

(क) विनिर्दिष्ट खास निविष्टियों रसायनों और संगंधित तेलों आदि का शुल्क मुक्त आयात पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।

(ख) दूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लॉग लाइन तंत्र के आयात को शुल्क की रियायती दरों पर अनुमत करना

(ग) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट मानदण्डों की शर्तों के साथ समुद्री खाद्य अपशिष्ट की निकासी हेतु स्व-निराकरण प्रक्रिया लागू करना।

उच्च प्रौद्योगिकी
उत्पाद निर्यात
संवर्धन स्कीम

(vii) अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु स्कीम शुरू की गयी है।

1ख.2 हटा दिया गया है

अध्याय - एक (ग)**व्यापार बोर्ड**

व्यापार बोर्ड	1.ग.1	विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड की स्पष्ट और सक्रिय भूमिका है।
विचारणीय विषय	1.ग.2	व्यापार बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :- 1) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना। 2) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा, बाधाओं का पता लगाना तथा निर्यात अर्जन को अधिकतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपाय सुझाना। 3) आयात व निर्यात के वर्तमान संस्थागत ढांचे की जाँच करना तथा बांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यावहारिक उपाय सुझाना। 4) आयात और निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा अधिकतम उपयोग हेतु ऐसी स्कीमों को तर्कसंगत और व्यवहारिक बनाने हेतु उपाय सुझाना। 5) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जाँच करना तथा देश के सामान व सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाना। 6) उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अध्ययन करवाना।
गठन	1.ग.3	सरकार व्यापार नीति के विशेषज्ञ अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति को व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। सरकार अन्य 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स के महासचिवों को पदेन सदस्य नियुक्त करेगी। व्यापार बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।
	1.ग.4	हटा दिया गया है।
	1.ग.5	हटा दिया गया है।
	1.ग.6	हटा दिया गया है।

अध्याय - दो**निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान**

- आयात और निर्यात मुक्त जब तक कि अन्यथा विनियमित न हो
- 2.1 निर्यात और आयात, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वे इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लागू अन्य कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं, मुक्त होंगे। मदवार निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित "आई टी सी(एच एस)" में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- 2.1.1 इराक से/ को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात निषिद्ध होगा।
- 2.1.2 कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य (डी पी आर) से/को निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात निषिद्ध है: -
- i) दस्तावेजों एस/2006/814, एस/2006/815 और एस/2006/853 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति दस्तावेज) में सूचीबद्ध सभी मदों, सामग्री उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जो डी पी आर को आणविक संबंधी बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा अन्य व्यापक जनसहार के हथियारों संबंधी कार्यक्रमों में योगदान दे सकता है।
- 2.1.3 सभी मदों, सामग्रियों, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात, जो ईरान के परिशुद्धता-संबंधी, पुनः संसाधन अथवा हैवी वाटर संबंधी कार्यकलापों में अथवा निम्नलिखित न्यूक्लीयर वीपन डिलिवरी सिस्टम्स के विकास में योगदान दे सकता है, चाहे उसका उद्गम देश ईरान हो या नहीं, निषिद्ध होगा :-
- i) दस्तावेज एस/2006/814 के आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी 8/भाग-1 में खण्ड ख.2 से ख.7 के साथ-साथ क.1 और ख.1 में शामिल उपकरण की आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानान्तरण जब ऐसे उपकरण क.1.2 में शामिल लाइट वाटर रिएक्टरों और लो-एनरिज यूरेनियम हेतु ऐसा उपकरण रिएक्टरों हेतु असेम्बलड न्यूक्लीयर फ्यूल एलीमेंट्स में शामिल हो;
- ii) श्रेणी-2 के 19.क.3 में शामिल मदों की आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानान्तरण को छोड़कर एस/2006/815 में सूचीबद्ध मदों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के उपर्युक्त दस्तावेज विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- कानून का अनुपालन 2.2 प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की शर्तों और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सभी आयातित माल बी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवश्यक किम्बरले प्रोसेस (के पी) प्रमाण-पत्र जब तक पोतलदान पार्सल के साथ संलग्न न हो, अनगढ़े हीरों का आयात अथवा निर्यात अनुमत नहीं होगा।
- नीति की व्याख्या 2.3 आई टी सी(एच एस) अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) अथवा डी ई पी बी दर की अनुसूची में किसी मद के वर्गीकरण, के संबंध में या इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
- प्रक्रिया 2.4 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेशों तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2), डी ई पी बी दर की अनुसूची और आई.टी.सी. (एच एस) में सम्मिलित होगी तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी। ऐसी प्रक्रियाओं को, इसी प्रकार, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।
- प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) विदेश व्यापार नीति की अनुपूरक है तथा इसमें सम्बद्ध प्रक्रियाओं और अन्य ब्यौरों का उल्लेख है। नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध लाभों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- नीति/प्रक्रिया से छूट 2.5 व्यापार में आने वाली वास्तविक दिक्कतों और प्रतिकूल प्रवाद को दूर करने हेतु महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या संमुचित हो, दे सकते हैं।
- महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति के किसी प्रावधान से या किसी

प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं या ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। इस अनुरोध पर केवल निम्न समितियों की सलाह के बाद ही विचार किया जाएगा :-

क्रमांक	विवरण	समिति
(i)	निजी स्कीमों के तहत उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानक समिति
(ii)	ई पी सी जी स्कीमों के तहत पूंजीगत माल और लाभों के साथ अन्तः संबंध	ई पी सी जी समिति
(iii)	अन्य सभी मुद्दे	नीति छूट समिति

प्रतिबंध के सिद्धान्त

2.6

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता :-

- (1) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण।
- (2) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
- (3) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम।
- (4) कैदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम।
- (5) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व मूल्य की राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण।
- (6) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण।
- (7) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण, और
- (8) हथियारों, गोला-बारूद और युद्ध के साज-सामान के व्यापार की रोकथाम।

प्रतिबंधित माल

2.7

कोई भी माल जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित किया गया है, उसका इस संबंध में जारी किए गए अनुमति पत्र या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

लाइसेंस/प्रमाण पत्र/
अनुमति/ प्राधिकार
की अनुमति की शर्तें

2.8

प्रत्येक अनुमति पत्र विनिर्दिष्ट वेधता अवधि के लिए वेध होगा तथा अनुमति पत्र में दी गई शर्तें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1. माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य,
2. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त,
3. निर्यात दायित्व,
4. प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संवर्धन,
5. न्यूनतम निर्यात आयात मूल्य

प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/
प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र
प्राप्त करने का अधिकार नहीं

2.9

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन अधिनियम) अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने से इंकार करने या नवीकरण नहीं करने का अधिकार होगा।

जुर्माना

2.10

यदि प्राधिकार पत्र धारक और विदेश व्यापार नीति प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे इस विदेश व्यापार (विकास व विनियमन अधिनियम) के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य व्यापार

2.11

कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) नामक पुस्तक में यथा- विनिर्दिष्ट अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है। तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है।

राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं। ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।

- आयातक-निर्यातक कोड संख्या. 2.12 जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा।
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार 2.13 महानिदेशक विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।
- माल लाने-ले-जाने की सुविधा 2.14 भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।
- ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार 2.15 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीम बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में दिया गया कुछ भी जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।
- वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 2.16 पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोग्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, हिस्से पुर्जे उपसाधित्र यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।
तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरूरत हों, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है बशर्ते कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यह शर्त समाप्त न कर दी गई हो।
- पुरानी वस्तुएं 2.17 पुराने पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी तथा उन्हें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों, आई टी सी(एच एस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के अनुसार उनका आयात किया जा सकता है।
पुनः सुसज्जित फरबिसड/पुनः प्रशीतक पुर्जे सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात मुक्त रूप से होगा तथापि पुराने व्यक्तिगत कम्प्यूटर/लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन, प्रशीतक, डीज़ल जनरेटिंग सेट का आयात लाइसेंस के मद्दे किया जाएगा।

		पुनः विनिर्मित वस्तुओं के आयात की अनुमति मुक्त रूप से केवल लाइसेंस के मद्दे होगी।
नमूनों का आयात	2.18	नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।
उपहारों का आयात	2.19	विदेश व्यापार नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी। अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी (सी सी पी) की अनुमति महानिदेशक, विदेश व्यापार से प्राप्त करनी होगी।
यात्री असबाब	2.20	वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों में उनकी शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है। ऐसी मर्दों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है। विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रूप में, उनके पास आए विशिष्ट निर्यात आर्डरों के लिए अपेक्षित ड्राइंग, पैटर्न्स, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्डस, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।
निर्यात के आधार पर आयात	2.21	नया अथवा पुराना पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों उनका सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है।
विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात	2.22	आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, अतिरिक्त पुर्जें, अनुसंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलौजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।
विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात	2.23	विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।
खुले समुद्र में बिक्री	2.24	भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन आयात	2.25	पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन नई पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है।
सीमाशुल्क से माल की निकासी	2.26	वह माल जो पहले ही आयातित/पोतलदान/पहुंच गया हो लेकिन सीमाशुल्क से उसकी निकासी न हुई हो उस माल को बाद में जारी प्राधिकार पत्र के प्रति निकासी की जा सकती है, को स्थापित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पिछली नीति से सम्बन्धित सभी शेष समस्याओं और विवादों को समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।
बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन	2.27	जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा। स्वदेशी प्राप्ति पत्र/प्राधिकार पत्र धारक को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को प्रस्तुत करना होगा।
	2.27.1	हटा दिया गया है।
आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम	2.28	<p>राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं।</p> <p>कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद या खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों में रख सकता है।</p> <p>ऐसी वस्तुओं की विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहाँ कहीं जरूरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे घरेलू खपत के लिए निकासी की जा सकती है। ऐसे माल पर निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।</p> <p>एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती तो इन वस्तुओं का आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।</p>
मुक्त निर्यात	2.29	आयात और निर्यात की आई.टी.सी.(एच.एस.) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किए जा सकते हैं।

तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है।

नमूनों का निर्यात	2.30	नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तके (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
यात्री असबाब का निर्यात	2.31	बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वस्तुतः निजी सामान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित तौर पर उल्लिखित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरूरी होगा।
उपहारों का निर्यात	2.32	किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में छाद्य मदों सहित 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा। तथापि, निर्यात की आई टी सी(एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता।
अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात	2.33	(आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित मदों के अलावा) संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के (स्वदेशी अथवा आयातित) वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के मद्दे निर्यात किया जा सकता है।
तीसरा पक्ष निर्यात	2.34	विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 में यथापरिभाषित अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी।
आयातित वस्तुओं का निर्यात	2.35	विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रूप में या अंशतः उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते आयात या निर्यात की जाने वाली मद आई टी सी (एच एस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित हो।
	2.36	आई टी सी(एच एस) में निर्यात अथवा आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

- प्रतिस्थापन माल का निर्यात 2.37 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मर्चों के तौर पर उल्लिखित न हो।
- मरम्मत किए गए माल का निर्यात 2.38 निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान को प्राधिकार-पत्र के बिना और समय-समय पर इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।
- निर्यात के लिए निजी वाण्डेड गोदाम 2.39 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी वाण्डेड गोदाम की स्थापना की जाए।
- निर्यात संविदाओं का कोटिकरण 2.40 सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा के वर्ग में रखा जाएगा परन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी।

ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे। अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते की उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

तथापि विशेष निर्यातों के प्रति निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय वॉस्ट्रों खाते के जरिए हों। इसके साथ वॉस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति हो।

जिन संविदाओं के लिए भुगतान एशियन क्लीयरिंग युनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे उन्हें ए सी यू डालर के वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्विज बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रति निर्यात ठेके और बीजक भारतीय रुपयों में किए जा सकते हैं।

- निर्यात प्राप्तियों की वसूली 2.41 यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
- निर्यात वस्तुओं की मुक्त आवाजाही 2.42 किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मर्दों की खेप को किसी भी कारण से रोका/बिलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता की मांग कर सकता है।
- स्टॉक को जब्त न करना 2.42.1 किसी भी अभिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जायेगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न डाली जा सके। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकती है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।
- निर्यात संवर्धन परिषद 2.43 निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- पंजीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र 2.44 कोई भी व्यक्ति जो आयात निर्यात के लिए (1) प्राधिकार पत्र (आई टी सी(एच एस) में प्रतिबंधित मर्दों के अतिरिक्त) (2) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बशर्त कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो।
- 2.45 हटा दिया गया है।
- ई डी आई पहल के जरिये व्यापार सुविधा 2.45.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय की कोशिश अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अमल में लाते हुए व्यापार दस्तावेजों के अधिकतम सरलीकरण, मानकीकरण और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए काम करना है। इस दिशा में विदेश व्यापार महानिदेशालय दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है जो सीमाशुल्क और बैंकों सहित अन्य संबंधित समुदाय के साथ संदेश के आदान प्रदान और सहमत प्रोटोकाल पर आधारित है।

डी जी सी आई और एस वाणिज्यिक व्यापार डाटा	2.45.2	प्रयोक्ताओं को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक निर्णय लेने के योग्य बनाने हेतु डी जी सी आई और एस द्वारा व्यवसायिक दृष्टिकोण से संरचना के प्रारूप पर आधारित न्यूनतम समय अन्तराल वाले व्यापार डाटा उपलब्ध किए जाएंगे।
ई डी आई पहल अनुकूलन के उन्नयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	2.45.3	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से, विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदनों और ई एफ टी (इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए आवेदन शुल्क के लिए आवेदन शुल्क में कटौती अनुमत होगी। ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में वर्णित है।
बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व घूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान	2.46	ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ऐसे कारणों जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और कमजोर इकाईयों के विलयन, अर्जन और पुर्नवास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में बंदोबस्त आयोग बनाने को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।
दस्तावेज अपेक्षाओं का सरलीकरण	2.47	अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए एकल सामान्य दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लंबित होने के कारण निर्यात-आयात से ढील करने वाले सरकारी विभाग जहाजरानी बिल, बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र, पैकिंग सूची, लदान बिल आदि जैसे निर्यात दस्तावेजों की जाँच के आधार पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र का स्वीकार करेंगे और इन दस्तावेजों को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं देंगे।
डी टी ए में सेवा कर की वापसी	2.48.1	प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के अध्याय-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ ये/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की अनुमति दी जाएगी।
एस ई जेड में सेवा कर से छूट	2.48.2	एस ई जेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट दी जाएगी।
विदेश व्यापार में ली गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट	2.48.3	भारत से निर्यातित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेश व्यापार में दी गई प्राप्त की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट होगी।

शिकायत निवारण

निर्यात/आयात के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय	2.49	विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधाकारक के रूप में कार्य करने को वचनबद्ध है। हमारा ध्यान बेहतर प्रशासन पर है जो कि स्वरूप, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है।
सिटीजन चार्टर	2.49.1	विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है इसमें ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय सारणी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के विवरण दिए गए हैं।
शिकायत निवारण प्रणाली	2.49.2	नीति और प्रक्रिया से संबंधित व्यापार और उद्योग जगत की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सरकारी संकल्प द्वारा एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। सरकार देशी को माफ करने वास्तविक मामलों में निर्यातकों द्वारा उत्लंघन को विनियमित करने, हकदारी पर उठे विवाद को सुलझाने, प्राधिकार-पत्र के प्रयोग हेतु विस्तार की स्वीकृति आदि के लिए 27.10.2004 को स्थापित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पिछली नीति से सम्बन्धित सभी शेष समस्याओं और विवादों का समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।
	2.49.3	हटा दिया गया है ।
अपरिहार्यता प्रावधान	2.50	यदि यूनिट/फर्म/कम्पनी अप्रत्याशित परिस्थितियों/और अपरिहार्यता प्रावधान के कारण नुकसान उठाती है तो निर्यात दायित्व अवधि और प्राधिकार की वैधता को वैधता अवधि समाप्त होने की तारीख से डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली उपयुक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र एसआईडीई योजना से अभिन्न महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना के अन्तराल को पहचानने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट निर्यात के अधिसूचित कस्बे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता	3.4.1	केन्द्र सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें। केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करेगी।
परीक्षण गृह	3.4.2	केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर के स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी।
गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/ विवाद	3.4.3	विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों की क्षेत्रीय उप-समिति (आर एस सी क्यू सी) द्वारा की जाएगी। विशेषतः गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु और सामान्यतः ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, दिशानिर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-16 में दिए गए हैं।
व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद	3.4.4	यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो <ol style="list-style-type: none"> (i) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक हो, और/अथवा (ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकर हो, और/अथवा (iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो, ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

3.5 निर्यात / व्यापार सदन

निर्यात और व्यापार सदन 3.5.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातमुखी एकक (ई ओ यू)/विशेष आर्थिक ज़ोन (एस ई जेड), कृषि निर्यात ज़ोन (ए ई जेड) में स्थित यूनिटें, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनॉलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर तकनॉलॉजी पार्क (एस टी पी) और जैव तकनॉलॉजी पार्क (बी टी पी) निर्यात और व्यापार सदन स्तर के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

स्तर श्रेणी 3.5.2 आवेदक की श्रेणी का निर्धारण चालू तथा पिछले तीन वर्षों के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रिफ पर्यन्त निःशुल्क मूल्य मान्य निर्यातों के लिए) निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा। निर्यात सदन स्तर के लिए चार वर्षों (अर्थात् चालू और पिछले तीन वर्षों हेतु) में से कम से कम दो वर्षों में निर्यात निष्पादन आवश्यक है।

स्तर श्रेणीएफ ओ बी/एफ ओ आर मूल्य
निर्यात-निष्पादन (रुपयों करोड़ में)

निर्यात सदन	20
स्टार निर्यात सदन	100
व्यापार सदन	500
स्टार व्यापार सदन	2500
डीलेक्स व्यापार सदन	10000

दोहरी वरीयता टिप्पणी 1. तघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ पंजीकृत यूनिट, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिट, हस्तकरघा, हस्त शिल्प, हाथ से बुना कालीन, रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा परिशिष्ट-9 में यथा सूचीबद्ध लेटिन अमेरिका/सी आई एस/उप सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, आई एस ओ 9000 (श्रृंखला) वाले यूनिट/आईएसओ 14000 (श्रृंखला) स्तर वाले/ डब्ल्यूएचओजीएमपी/एचएसी सीपी/एसईआईसीएमएम स्तर-2 तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो परिशिष्ट 6क में सूचीबद्ध की गई हैं। सेवा और कृषि उत्पादों के निर्यात, स्टार निर्यात सदन स्तर की स्वीकृति हेतु, निर्यात के दोहरे वरीयता के पात्र होंगे। यह लाभ विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यातकों को ही उपलब्ध होगा। तथापि, एक पोत-लदान उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी एक को केवल एक पोत-लदान के लिए दोहरी वरीयता दी जाएगी।

- 1(क) निर्यात कारोबार एक से दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अतः निर्यात उत्पादन की गणना के लिए डिसक्लेमर पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं की जाएगी।
3. मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर होने चाहिए।
4. हटा दिया गया है।

विशेषाधिकार

3.5.2.1 एक स्तर धारक निम्नलिखित सुविधाओं को हकदार होगा :-

- (i) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी।
- (ii) तरजीह पर निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण 60 दिन के भीतर।
- (iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट, तथापि बैंकिंग चैनलों से रुपया भेजना जारी रहेगा।
- (iv) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा।
- (v) सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से 360 दिन तक करना।
- (vi) हटा दिया गया है।
- (vii) विदेश व्यापार नीति के अधीन योजनाओं में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी।
- (viii) एस ई एच और उपयुक्त को राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात बेयरहाउसिंग (गोदाम) बनाने की अनुमति होगी।

3.5.3 हटा दिया गया है।

	3.6	सेवाओं का निर्यात
सेवा निर्यात	3.6.1	सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाली सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं शामिल हैं। यहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है। सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट - 10 में दी गई हैं।
सेवा प्रदायकों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र	3.6.2	साफ्टवेयर निर्यातकों को इलेक्ट्रानिक और साफ्टवेयर ई पी सी के पास पंजीकरण करवाना होगा। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-2 की क्रम सं० 34 में सूचीबद्ध 13 विशिष्ट सेवाओं के निर्यातकों को सेवा ई पी सी के पास पंजीकृत करवाना होगा। अन्य सेवा निर्यातकों को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन के पास पंजीकृत करवाना होगा।
आम सुविधा केन्द्र	3.6.3	सरकार क्षेत्र विशेष में गृह आधार पर सेवा प्रदायकों जैसे इंजिनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, मल्टी-मिडिया कार्यक्रमों, साफ्टवेयर का विकास करने वालों आदि के उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी तथा राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात नजरिये में गृह आधारित व्यावसायिकों को दारी संख्या में बुलाया जायेगा।
	3.6.4	भारत से सेवित स्कीम
उद्देश्य	3.6.4.1	सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य है ताकि सशक्त और विशिष्ट "भारत से सेवित" बांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो जाए।
पात्रता	3.6.4.2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-10 में सूचीबद्ध सेवाओं के सभी सेवा प्रदायक जिनका कुल मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपये है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे। अलग-अलग सेवा प्रदायक के लिए न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपये होगी।
हकदारी	3.6.4.3	सभी सेवा प्रदायक (पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा प्रदायकों के अलावा) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 3.18.1 में यथा सूचीबद्ध सेवाएं और सेवा प्रदायक हकदार नहीं होंगे।
प्रेषण	3.6.4.3.1	सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य उपकरणों के जरिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के परिकलन के लिए अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा को भी ध्यान में रखा जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में
होटल, रेस्टोरेंट एवं
अन्य सेवा प्रदायक

- 3.6.4.4 पर्यटन विभाग, द्वारा अनुमोदित एक सितारा और उससे अधिक सितारा होटल (मैनेज्ड होटल और हैरिटेज होटल शामिल हैं) और पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक विगत वित्तीय वर्ष में अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।

विशिष्ट रेस्टोरेंट विगत वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।

अनुमत आयात

- 3.6.4.5 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोग्यों जो कि अन्यथा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं। आयात आवेदक के किसी सेवा क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित होगा।

अर्जित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के इस्तेमाल की अनुमति वाहनों के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी के लिए नहीं दी जाएगी, चाहे आई टी सी (एच एस) के तहत ऐसे वाहन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

होटलों, गोल्फ रिजार्ट, क्लबों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में, जहाँ कैटरिंग सुविधा हो; शुल्क क्रेडिट स्क्रिप खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।

गैर-हस्तांतरणीयता

- 3.6.4.6 हकदारी माल (आयातित/प्राप्त) गैर-हस्तांतरणीय होगा। (ग्रुप कम्पनी और प्रबन्धित होटलों के भीतर को छोड़कर) और वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

3.6.4.7
से

- 3.6.4.9 हटा दिया गया है।

घरेलू स्रोतों से प्रापण

- 3.6.4.10 पैरा 3.6.4.5 के अधीन अनुमत मदों के घरेलू स्रोतों से प्रापण हेत इस संबंध में जारी राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

3.7 हटा दिया गया है।

- 3.8 विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग उपज योजना (विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना)

- उद्देश्य** 3.8.1 विशेष कृषि और ग्रामीण उद्योग योजना निम्नलिखित उद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- (1) कृषि उत्पाद और इनके मूल्य वर्धित उत्पाद;
 - (2) 1.4.2004 से निर्यात हेतु लघु वन्य उपज और उनके मूल्य वर्धित परिवर्ती;
 - (3) 1.4.2006 से निर्यात हेतु ग्राम उद्योग उत्पाद और
 - (4) 1.4.2007 से निर्यात हेतु वन आधारित उत्पाद ऐसे उत्पाद प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट 37 क में सूचीबद्ध ऐसे उत्पाद।

- हकदारी** 3.8.2 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ अधिक परिवहन लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान की जाती है। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की परिशिष्ट 37 क में अधिसूचित उत्पादों के निर्यातक, निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होंगे (मुक्त विदेशी मुद्रा में उपार्जित)।

तथापि इस स्कीम के अधीन निर्यात मद से संबंधित ऐसे मामले में जहाँ कृषि निवेशों (उत्प्रेरक, उपभोज्य और पैकिंग सामग्री को छोड़कर) के आयात के लिए इस नीति के अध्याय-4 के तहत निर्यातकों ने लाभ उठाए, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य मुक्त विदेशी मुद्रा में उपार्जित के 3.5 प्रतिशत की घटी दर पर प्रदान की जाएगी।

निर्यात की अवधि हेतु हकदारी प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में दी गई है।

तथापि, दिनांक 1.4.2007 से प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37क में अधिसूचित/दर्शाए अतिरिक्त उत्पाद निर्यात की सीमा शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होगी यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

- 3.8.2.1 ई ओ यू/बी टी पी द्वारा किया गया निर्यात जो प्रत्यक्ष कर लाभ/छूट प्राप्त नहीं करते हैं वे पात्र होंगे बशर्ते वे पैराग्राफ 3.8.2.2 के अधीन न आते हों।

- 3.8.2.2 निम्नलिखित निर्यात पर शुल्क क्रेडिट हकदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा :

क) (i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात;

- (ii) ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात अर्थात् निर्यात तीसरे देश से हुआ हो किन्तु भारत के माध्यम से भेजा गया हो;
- ख) मान्य निर्यात;
- ग) एस ई जेड इकाइयों से किया गया निर्यात; और
- घ) मर्चें जो निर्यात व आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में निर्यात नीति की अनुसूची 2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध हैं।

3.8.3 हटा दिया गया है।

से

3.8.5

3.8.6

सभी स्तर सरकारों को कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि - संसाधन के लिए कृषि निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य के 10 प्रतिशत सीमा तक शुल्क मुक्त आयात/पूँजीगत माल का आयात बुनियादी सुविधाओं की लागत के बराबर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन कृषि, कृषि मर्चों और कृषि - संसाधन जैसे कार्यकलापों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु कृषि मंत्रालय और अग्यों द्वारा नियंत्रित अन्य योजनाओं के लिए दिए जा रहे लाभ के अलावा है :

- (i) प्याज आदि के लिए कंट्रोल्ड एटमोस्फीयर (सी ए) और मोडिफाइड एटमोस्फीयर (एम ए) स्टोर्स, ग्री - कूलिंग यूनिट्स, और मदर स्टोरेज सहित कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स।
- (ii) पैक हाउसेज (हैंडलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग आदि की सुविधाओं सहित), और
- (iii) रीफर वेन/कन्टेन्स।

3.9 बाजार केन्द्रित स्कीम

उद्देश्य

3.9.1

इस स्कीम का उद्देश्य इन देशों को हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से ऊँचे वहन-शुल्क की कीमत तथा अन्य असमर्थताओं की क्षतिपूर्ति करता है।

हकदारी

3.9.2

अधिसूचित देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की परिशिष्ट 37ग में दिए अनुसार ई डी आई समर्पित पत्तों के माध्यम से सभी उत्पादों का

निर्यात 01 अप्रैल, 2006 से शुरु होने वाले प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा।

तथापि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की परिशिष्ट 37g में अधिसूचित अतिरिक्त बाजार 1.4.2007 से निर्यातों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु हकदार होगा।

3.9.2.1 ई ओ यू/ई एच टी पी/बी टी पी द्वारा किए गए निर्यात जो प्रत्यक्ष कर लाभ/छूट प्राप्त नहीं करते हैं वे पात्र होगी, बशर्ते वे पैराग्राफ 3.9.2.2 के अन्तर्गत कवर नहीं हैं।

3.9.2.2 निम्नलिखित निर्यातों पर हकदारी की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा;

क)(1) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल के निर्यात या

(2) ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात अर्थात् निर्यात मूल रूप से तीसरे देश से हुआ हो किन्तु भारत से भेजा गया हो।

ख) एस ई जेड एककों का निर्यात कारोबार अथवा इन एककों को की गयी आपूर्तियाँ अथवा डी टी ए इकाइयों के जरिये निर्यातित एस ई जेड उत्पाद।

ग) मान्य निर्यात

घ) सेवा निर्यात

ड.) हीरे और अन्य कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थर

च) स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम और सादे और जड़ित आभूषण सहित किसी भी रूप में अन्य कीमती पत्थर।

छ) सभी रूप में और सभी प्रकार के अयस्क और सांद्रण।

ज) सभी प्रकार के अनाज

झ) सभी प्रकार की और सभी रूपों में चीनी,

ञ) सभी प्रकार के और सभी रूपों में कच्चे/पेट्रोलियम और कच्चे तेल/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो आई टी सी(एच एस) कोड 2709 से 2715 में शामिल किए गए हैं।

- ट) मदे जो निर्यात व आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध है।

3.9.2.3 हटा दिया गया है।

3.9.3 से हटा दिया गया है।

3.9.6

3.9.3 से हटा दिया गया है।

3.9.6

3.10 उत्पाद केन्द्रित स्कीम

उद्देश्य

3.10.1 स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है जिनकी ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उच्च रोजगार प्रगाढ़ता है जिससे मूलभूत सुविधाओं में कमी तथा इन उत्पादों के विपणन में आयी अन्य सहबद्ध कीमतों की क्षतिपूर्ति की जा सके।

पात्रता

3.10.2 सभी देशों को ईओआई समर्थित पत्तनों के माध्यम से अधिसूचित उत्पादों का निर्यात (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट-37घ में दिये गए अनुसार) 1 अप्रैल, 2006 से शुरू होने वाले प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए निर्यात के पोट पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.25 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-37घ में अधिसूचित अतिरिक्त उत्पाद 1-4-2007 के बाद किए गए निर्यात पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होंगे।

3.10.2.1 ई ओ यू/ई एच टी पी/बी टी पी द्वारा किए गए निर्यात जो प्रत्यक्ष कर लाभ/छूट प्राप्त नहीं करते हैं वे पात्र होंगी, बशर्ते वे पैराग्राफ 3.10.2.2 के अन्तर्गत कवर नहीं हैं।

3.10.2.2 स्कीम के तहत निर्यात निष्पादन के आकलन अथवा हकदारी की गणना के लिए निम्नलिखित निर्यातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

क) (i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात

(ii) ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात अर्थात् निर्यात मूल रूप से तीसरे देश से हुआ किन्तु ट्रांसशिपड भारत से किया गया हो,

ख) एस ई जेड एककों का निर्यात कारोबार अथवा इन एककों को की गयी आपूर्तियाँ अथवा डी टी ए इकाइयों के जरिये निर्यातित एस ई जेड उत्पाद: और

ग) मान्य निर्यात

3.10.2.3 हटा दिया गया है।

3.10.3 से

3.10.6 हटा दिया गया है।

3.11 उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम।

उद्देश्य

3.11.1 उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया देना है।

हकदारी

3.11.2 अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी की उत्पादों (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट-37ड. में यथा अधिसूचित) का निर्यात सभी देशों के उन पत्तनों के माध्यम से अनुमित होगा जो इ डी आई से जुड़े हुए है 1 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के लिए पूर्व वर्ष (अर्थात 2006-07) की तुलना में चालू वर्ष (अर्थात 2007-08) हेतु अधिसूचित उत्पादों, (मुक्त विदेशा मुद्रा में प्राप्त) के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि के 10 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होगा।

3.11.3 निम्नलिखित आधार पर निष्पादन की गणना की जाएगी:-

- (i) अधिसूचित उत्पादों का एक साथ किया गया निर्यात
- (ii) प्राप्त जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (जैसा कि बी.आर.सी/एफ आई आर सी में प्रतिबिम्बित है।)
- (iii) आधार वर्ष में शून्य निर्यात वाले आवेदक पात्र नहीं होंगे।

अधिकतम सीमा

3.11.4 लाइसेंसिंग वर्ष में किए गए सभी पोतलदानों हेतु निर्यातक के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा जिसके लिए इस स्कीम के अन्तर्गत लाभों का दावा किया जा रहा है।

अपात्र निर्यात/श्रेणियाँ

3.11.5 हकदारी के लिए निम्नलिखित की गणना नहीं की जाएगी:-

- (i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात:
- (ii) तीसरे देश में होने वाले निर्यात किन्तु भारत से भेजा गया हो,

(iii) एस ई जेड यूनिटों का निर्यात या डी टी ए यूनिटों के जरिये निर्यात किए गए एस ई जेड उत्पाद और

(iv) मान्य निर्यात

3.12 इस अध्याय के अन्तर्गत स्कीमों पर लागू सामान्य प्रावधान, उन्हें छोड़कर जहां विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए हो।

सेनवेट/शुल्क वापसी

3.12.1 एस एफ आई एस के अन्तर्गत आने वाले को छोड़कर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद या डेबिट में अदा अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क राजस्व विभाग नियमावली के अनुसार सेनवेट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।

विशेष प्रावधान

3.12.2 लोकहित में सरकार को ऐसे देशों को निर्यात उत्पाद या सेवाएँ या निर्यात विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है जो हकदारी की गणना के लिए पात्र नहीं होगी इसके अतिरिक्त सरकार को इस अध्याय के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर अधिकतम सीमा बदलने का अधिकार है। इसी प्रकार सरकार सामान (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट-37ख में) को भी अधिसूचित कर सकती है जिसे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन आयात की अनुमति नहीं होगी।

टी आर ए सुविधा

3.12.3 राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) के अन्तर्गत पंजीकरण के घटन से इतर घटन से आयातों के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग।

अनुमित आयात

3.12.4 पूंजीगत माल सहित निविष्टियों या माल के आयात के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते उसका आई टी सी (एचएस) के अन्तर्गत मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 की परिशिष्ट-37ख में सूचीबद्ध मर्दों का आयात डेबिट किए जाने के लिए अनुमति नहीं होगी।

मुक्त हस्तांतरणीयता

3.12.5 एस एफ आई एस के अधीन आने वालों को छोड़कर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप और उसके मद्दे आयातित मर्दें मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी।

हकदारी की विशिष्टता

3.12.6 पोटलदान के लिए इस अध्याय में शामिल किसी भी स्कीम के अन्तर्गत लाभों का केवल निर्यातक के विकल्प पर ही दावा किया जा सकता है।

लीज वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात

3.12.7 विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.25 के प्रावधानों में लीज वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

निर्यात निष्पादन का
अन्तरण

- 3.12.8 एक से दूसरे को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार, पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो उसकी निर्यात निष्पादन/आवेदक के कारोबार की गणना की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और इसको बी आर सी/ एफ आई आर सी से प्रमाणित करना होगा।

अध्याय - चारशुल्क छूट और शुल्क विमुक्ति स्कीम

- शुल्क छूट और विमुक्ति स्कीम 4.1 शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र और (ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ई) प्रमाणपत्र शामिल है। शुल्क छूट स्कीम निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क के निर्यात के पश्चात प्रतिपूर्ति/ छूट की जाती है। शुल्क छूट स्कीम (क) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम/ डी ई पी बी) और (ख) शुल्क वापसी स्कीम (डी बी के) हैं।
- शुल्क छूट/विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का पुनः आयात 4.1.1 अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र/डी एफ आर सी/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का पुनः आयात उसी रूप या आंशिक रूप से उसी रूप में पुनः आयात राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जा सकता है।
- मूल्य संवर्धन 4.1.2 इस अध्याय के मामले में (रत्न और आभूषण छोड़कर) मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :-
- $$\text{वी.ए.} = \frac{\text{ए-बी}}{\text{बी}} \times 100, \text{ जहाँ}$$
- ए किए गए वास्तविक निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति के मार्ग पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए
- बी प्राधिकार पत्र के तहत आने वाले आयातित निवेशों का लागत भीमा भाड़ा मूल्य तथा कोई अन्य प्रयुक्त आयातित माल जिसपर शुल्क वापसी का लाभ का दावा किया गया है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम

- अग्रिम प्राधिकार पत्र 4.1.3 निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की जाने वाली निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा, ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैंटालिस्ट आदि जिनकी खपत/प्रयोग निर्यात उत्पाद के लिए किया जाता है, को अनुमत किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, अग्रिम प्राधिकार पत्र को सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को हटा सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे अनिवार्य कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनका परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति आवश्यक है। शियान (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तथापि, वे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित मानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र सहायक विनिर्माता के साथ जुड़े विनिर्माता निर्यातक, अथवा व्यापारी निर्यातक को निम्नलिखित हेतु जारी किया जा सकता है :-

- i. वास्तविक निर्यात (एस ई जेड को किए निर्यात समेत); और/या
- ii. अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ, और/या
- iii. नीति के पैरा

8.2(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ) और (ज) में उल्लिखित श्रेणियों को माल की आपूर्ति;

- iv. विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर सामान की आपूर्ति इस शर्त के मद्दे होगी कि संभरित मदों के संबंध में विशिष्ट शियान है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(घ)(ङ)(च)(छ) और (ज) पैराग्राफ में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के बारे में, ऐसी परियोजना के उप-ठेकेदार द्वारा भी अग्रिम प्राधिकार पत्र का लाभ उठाया जा सकता है बशर्ते की उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो।

ऐसा प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को की गयी आपूर्तियों के अन्तर्गत हेतु भी जारी किया जा सकता है और जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

- 4.1.4 अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। ऐसे प्राधिकार पत्र मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त होंगे। तथापि, पैरा 8.2(ज) और (झ) के तहत शामिल आपूर्तियों हेतु आयात, लागू एंटी-डम्पिंग और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगा।

4.1.5 अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा उनके तहत आयातित माल वास्तविक उपयोक्ता शर्त के साथ होगा। यह निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी हस्तान्तरणीय नहीं होंगे। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के बाद शुल्क मुक्त निवेशों में से विनिर्मित उत्पाद को बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।

4.1.6 अग्रिम प्राधिकार पत्र सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात की अपेक्षा करता है। एस ई जेड यूनिटों को निर्यात/विकासकों/सह-विकासकों को आपूर्ति, वसूली की मुद्रा चाहे कोई भी हो, भी शामिल होगी।

ऐसा वास्तविक निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है, वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

चाय के आयात के लिए प्राधिकार पत्र के मामले में अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत न्यूनतम मूल्य संवर्धन 100 प्रतिशत होगा।

इसी प्रकार मसालों के मामले में (निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) मसालों के शुल्क मुक्त आयात के मामले में अनुमति केवल मूल्य संवर्धन प्रयोजनों जैसे कृषिग/ग्राइन्डिंग स्टेसीलाइजेशन या आयाल्स और ओलिया रेजिन्स के विनिर्माण हेतु और सिर्फ क्लीनिंग, ग्रेडिंग, शीपकेजिंग आदि के लिए अनुमति नहीं होगी और न्यूनतम मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत होगा।

4.1.7 अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को प्रभावी प्रक्रिया और नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा
आपूर्ति निःशुल्क

4.1.8 अग्रिम प्राधिकार पत्र की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ अथवा सभी निवेशों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु निःशुल्क निवेशों के नोशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निवेशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, यदि सभी निविष्टियों की बिना लागत आपूर्ति की जाती है तो निर्यातक के पास राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करने का भी विकल्प होगा।

निर्यात दायित्व 4.1.9 अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित अनुसार होंगी।

बी आई एफ आर 4.1.9क बी आई एफ आर के पास पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी अथवा यूनिट अधिग्रहण करने वाली किसी फर्म/कम्पनी, जो बी आई एफ आर के अन्तर्गत हो, उसे बी आई एफ आर के अनुमोदन की शर्त के अधीन, तैयार किए पुनर्वास पैकेज के अनुसार निर्यात निष्पादन अवधि विस्तार या संयोजन शुल्क की अदायगी के बिना 5 वर्ष यदि विनिर्दिष्ट न हो की अनुमति होगी बशर्ते कि बी आई एफ आर का बाद में अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

उपर्युक्त प्रावधान लघु उद्योग इकाइयों पर संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अनुसार लागू होते हैं।

वार्षिक आवश्यकता 4.1.10 अग्रिम प्राधिकार पत्र वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।
के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

स्तर प्रमाणपत्र धारक और निर्यातकों की अन्य सभी श्रेणियां जिनका विगत निर्यात निष्पादन (पिछले दो वर्षों का) हो वे भी वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु पात्र होंगे।

आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनुसार हफ्तवारी वास्तविक निर्यात और/या मान्य निर्यात के मूल्य के पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 300 प्रतिशत अथवा एक करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, तक होगी।

अग्रिम रिलीज आदेश
और अवैधीकरण
प्रमाण पत्र

4.1.11 अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र का धारक और डी एफ आई ई प्रमाणपत्र का धारक जो सीधे आयात के बदले स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार अभिकरणों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेश अवैधीकरण प्रमाणपत्र के प्रति मुक्त विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। तथापि, ई.ओ.यू./ई.एच.टी.पी./बी.टी.पी./एस.टी.पी./एस ई जैड युनिटों से ए.आर.ओ को परिवर्तन किए बिना प्राधिकार पत्र के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी एफ आई ए के अन्तर्गति ए आर ओ सुविधा के लिए भी पात्र होगा।

ए. आर. ओ की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित के अनुसार होगी।

बैंक टू बैंक
अन्तर्देशीय साख पत्र

4.1.12 अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, डी एफ आई ई प्रमाण पत्र धारक और हीरा अग्रदाय

प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम रिलीज आदेश अवैधीकरण पत्र के लिए आवेदन करने के बजाय, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है।

निषिद्ध मर्दे

4.1.13

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाण पत्र के तहत आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित आयातों का निषिद्ध मर्दों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मर्दों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र के मर्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मर्दे अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा अवैधीकरण पत्र के मर्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं।

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई प्रमाणपत्र धारक को समुद्र में बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य उद्यमों को भी प्रदान की जाती है।

डी ई आई ए धारक

प्राधिकार पत्र धारक को उन 'अन्तर्गति प्रमाणपत्र' के मर्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य उद्यमों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और राज्य व्यापार उद्यम, इसके बाद ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु डी जी एफ टी को एक पृष्ठांकित प्रति सहित संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगी।

इसी प्रकार आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित निर्यातों की निषिद्ध मर्दों का इस अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रमाणपत्र/डी एफ आई ए स्कीम के अन्तर्गत निर्यात नहीं किया सकता। प्रतिबंधित मर्दों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता अथवा सभी शर्तों के मर्दे आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत होगा।

शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

4.1.14

अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, निर्यातित माल में प्रयुक्त शुल्क भुगतान किए गए माल पर शुल्क वापसी उपलब्ध होगी, चाहे आयातित या स्वदेशी हो, वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। तथापि, आवेदन पत्र में यथाउल्लिखित शुल्क प्रदत्त सामग्रियों को ही शुल्क वापसी दी जाएगी।

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति

प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी)

4.2 से हटा दिया गया है।

4.2.8 तक

4.2.9 निर्यातों के लिए 1.5.2006 से स्कीम वापस ले ली गई है। 30.4.2006

तक किए गए निर्यात विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 के अधीन होंगे।
(31.3.2007 तक यथा संशोधित)

शुल्क हकदारी पास बुक (डी ई पी बी) स्कीम

शुल्क हकदारी पास
बुक स्कीम (डी ई पी बी)

4.3 शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। सेनेवेट क्रेडिट की अनउपलब्धता के मामले में ईंधन पर विशेष अतिरिक्त शुल्क और सीमाशुल्क का हिस्सा डी ई पी बी दर में भी कारक होगा। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के मदे शुल्क क्रेडिट की मंजूरी से किया जाएगा।

4.3.1 डी टी ए द्वारा एस ई जेड यूनिट को आपूर्ति के मामले में एस ई जेड यूनिट/एस ई जेड विकासक के विदेशी मुद्रा लेखा से डी ई पी बी के अधीन निर्यातक, मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के रूप में क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और ऐसी दरों के मदे उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों। क्रेडिट का इस्तेमाल किसी मद पर सीमाशुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है जो मुक्त रूप से आयात किए जा सकें।

4.3.2 डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नगद भी करने का विकल्प होगा।

वैधता

4.3.3 आयात के लिए डी ई पी बी की वैधता की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित के अनुसार होगी।

हस्तांतरणीयता

4.3.4 डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मदे मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण डी ई पी बी में आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।

निर्यात के पत्तन से अलग पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग अधिसूचना की शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के तहत अनुमति दी जाएगी।

शुल्क वापसी
की उपयुक्तता

4.3.5 डी ई पी बी के अधीन निविष्टियों डेविट के माध्यम से अथवा पर नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवेट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) स्कीम

- स्कीम** 4.4.1 निविष्टियों, ईंधन, तेल ऊर्जा स्रोत, उत्प्रेरक आदि के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी के लिए एक शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) पत्र जारी किया जाता है जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। महानिदेशक, विदेश व्यापार में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से डी एफ आई ए की सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को बाहर कर सकते हैं। यह स्कीम 01 मई, 2006 से प्रभावी होगी।
- हकदारी** 4.4.2 डी एफ आई ए के मामले में पैराग्राफ 4.1.3 के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, ये प्राधिकार पत्र उन उत्पादों के लिए जारी किए जाएंगे जिनके लिए निविष्टि और उत्पादन मानदण्ड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।
- पश्च निर्यात डी एफ आई ए के मामले में व्यापारी निर्यातक को उस विनिर्माता (विनिर्माताओं) के नाम और पते का उल्लेख करना अपेक्षित होगा जिससे निर्यात उत्पाद प्राप्त किए गए थे। डी एफ आई ए के तहत निर्यात करने से पहले आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- पूर्व निर्यात प्राधिकार पत्र वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे तथा मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एण्टी डम्पिंग शुल्क और सुरक्षात्मक शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- आयात मर्दे** 4.4.3 डी एफ आई ए धारक के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 और 4.1.14 के प्रावधान लागू होंगे।
- मूल्य संवर्धन** 4.4.4 रत्न और आभूषण क्षेत्र के मर्दों को छोड़कर ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अपेक्षित होगा, जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 4क.2.1 में यथा उल्लिखित मूल्य संवर्धन और अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अन्तर्गत जिन मर्दों के लिए अधिक मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, लागू होंगे।
- निर्यात दायित्व** 4.4.5 स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने से संबंधित प्रक्रिया और समय सीमा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के अध्याय 4 में दी गई है।
- हस्तान्तरणीयता** 4.4.6 निर्यात दायित्व पूर्ण हो जाने के बाद प्रमाणपत्र के हस्तान्तरणीयता अथवा इसके मद्दे आयातित निविष्टियों के लिए आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद प्राधिकार पत्र धारक, डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित ईंधन और अन्य

मद (मदों) के अलावा डी एफ आई ए अथवा शुल्क मुक्त निविष्टियों का हस्तान्तरण कर सकता है।

तथापि, ईंधन के लिए आयात हकदारी केवल उन कम्पनियों को हस्तान्तरित की जाएगी जिन्हें तेल और प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार पत्र मंजूर किया गया है। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्राधिकार पत्र अथवा आयातित निविष्टियों के हस्तान्तरण के मद्दे किए गए आयात लागू अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान करने की शर्त पर होंगे। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित करते समय पावती पत्र में ऐसी अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क की देयता संबंधी नोट लिखा होगा। ऐसे अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पादशुल्क को दामसी के तौर पर निर्यातक को प्रतिपूर्ति करनी होगी। उत्पाद शुल्क एकक द्वारा स्थानीय बिक्री के मामले में सेनवेट शुल्क पहले ही अदा किए गए उत्पाद शुल्क के बराबर होगा।

जहाँ कहीं सिआन वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित करता है और एसिटिक एनहाइड्राईड, इफेड्राईन और स्यूडो इफेड्राईन के मामले में, इन निविष्टियों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ डी एफ आई ए जारी किए जाएंगे तथा निर्यात दायित्व पूरा करने के बाद भी इन निविष्टियों हेतु कोई हस्तान्तरणीय अनुमत नहीं होगी।

सेनवेट सुविधा	4.4.7	आयातित या घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों हेतु सेनवेट क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी।
	4.4.8	हटा दिया गया है।

रत्न और आभूषण

रत्न और आभूषण के लिए स्कीम	4क	रत्न और आभूषण निर्यातक, रत्न और आभूषण के विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात प्राप्त कर सकते हैं।
प्रतिपूर्ति प्राधिकार	4क.1	रत्न और आभूषण निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति प्राधिकार (आर ई पी) प्राप्त कर सकते हैं।
	4क.1.1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 के अनुसार उपभोक्त्यों हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार जारी किए जा सकते हैं।

प्रतिपूर्ति प्राधिकार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उपभोक्त्यों के आयात के लिए भी जारी किया जा सकता है।

प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हीरों का निर्यात	4क.2	0.25 कैरेट और उससे अधिक के हीरे के प्रमाणन/ग्रेडिंग हेतु प्राधिकृत प्रयोगशालाएं निम्नवत हैं- (i) इंडियन डायमण्ड इंस्टिट्यूट, सूरत, गुजरात (ii) जेमोलाजिकल इंस्टिट्यूट आफ अमेरिका (जीआईए) (iii) दि राबर्ट मोवाड कैम्पस, इन्टरनेशनल जेमोलाजिकल इंस्टिट्यूट (आईजीआई) यू एस ए (iv) यूरोपियन जेमोलाजिकल लेबोरेटरी (ईजीएल), यू एस ए (v) होग रोड वूर डायमण्ड एन्टवर्क (एचआरडी) (vi) वर्ल्ड डायमण्ड सेन्टर आफ डायमण्ड्स हाई काउन्सिल, एन्टवर्प, बेल्जियम, (vii) सेन्ट्रल जेम लेबोरेटरी, 0 मियागी बिल्डिंग, 5-15-14 उएनो टोटे-कू, टोकियो, जापान (viii) अमेरिकन जेम सोसाइटी लेबोरेटरीज (एजीएस लेबोरेटरीज), 8917 वेस्ट सहारा एवेन्यू, लासवेगास, नेवादा 89117 (ix) डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी मैडेनहीड यू.के. और (x) इंटरनेशनल डायमण्ड लेबोरेटरीज डीएमसीसी, दुबई।
स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम के आभूषणों के लिए स्कीमें	4क.3	4क.2.1 एक निर्यातक (जिसका पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ का वार्षिक निर्यात कारोबार है) राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कटे और पॉलिश हीरों (0.25 कैरेट या अधिक) का विदेश में उम्पर दी गई एजेन्सियों/प्रयोगशालाओं को पुनः आयात सुविधा के साथ 3 महीनों के भीतर शुन्य शुल्क पर निर्यात कर सकते हैं। स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, प्लेटिनम, चांदी, मार्बेटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती इत्थर सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।
नामित एजेंसियां	4क.4	नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी) डीलक्स ट्रेडिंग हाउस और पैराग्राफ 3.5.2 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी। निर्यातक (ई ओ यू/एस

ई जेड स्कीम के तहत संचालित ईकाइयों को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित मार्ग निर्देशों के अनुसार मानक स्वर्ण छड़ों के रूप में शोधन और आयात हेतु स्वर्ण छीजन का आयात कर सकता है।

निर्यात की मंदा

4क.5

निम्नलिखित मदों का, यदि निर्यात किया जाता है, तो वे इन सुविधाओं के लिए पात्र होंगी : (क) 8 कैरेट या अधिक सोना या सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं) (ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले आंशिक रूप से संसाधित आभूषण सहित चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन, चांदी के स्ट्रिप्स और वस्तुएं इसमें मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वैद्य टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं हैं)। (ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

मूल्य परिवर्धन

4क.6

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य परिवर्धन (बी ए) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2.1 में दिए अनुसार होगी। इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:-

$$\text{बी.ए.} = \frac{\text{ए-बी}}{\text{बी}} \times 100, \text{ जहाँ}$$

ए = प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

बी = निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्त सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम अंश का मूल्य/जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी लागत बीमा भाड़ा मूल्य में शामिल किया जाएगा।

छीजन मानदंड

4क.7

सोने/चांदी/प्लेटिनम जेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा छीजन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा
आपूर्ति के प्रति निर्यात

4क.8

जहाँ निर्यात आदेश, तीन वर्ष के अनुभव वाले नामित एजेंसी/स्तर धारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ का कारोबार किया है, को दिया जाता है वहाँ विदेशी क्रेता विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम, एलॉय, चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की फाईंडिंग्स और माउंटिंग का अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप में नामित एजेंसियों/स्तर धारकों/निर्यातकों को आपूर्ति कर सकता है।

ऐसी आपूर्तियाँ अग्रिम तौर पर की जा सकती हैं और इनमें अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण जिनमें मसम्मत/पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाईंडिंग/माउंटिंग/कम्पोनेन्ट्स शामिल हैं, बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत हो। तथापि, यदि इस प्रकार के आयातित अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों का जड़ित आभूषण के रूप में निर्यात किया जा सकता है। उनका मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। निर्यात के ऐसे मामलों में 2 प्रतिशत के छीजन की अनुमति होती है।

नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियाँ या स्तरधारियों/निर्यातकों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाईंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा।

नामित एजेंसियों द्वारा
आपूर्ति के प्रति निर्यात

4क.9

निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र
के प्रति निर्यात

4क.10

निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र दिया जा सकता है :-

- (क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स।
- (ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।
- (ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

4क.11

ऐसे प्राधिकार पत्र को निर्यात दायित्व की शर्त रहेगी जिसे इस संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र 4क.12 विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.8, 4क.9 और 4क.10 में दिए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्न प्रतिपूर्ति (रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति) प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी जेवरों और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे प्राधिकार पत्र का मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद 4क.13 प्रतिपूर्ति की दर और आयात की मद, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 12ख के अनुसार निर्धारित होगी।

हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र 4क.14 कटे और पालिश किये हीरों, आधे कटे हीरे, किसी भी रूप में कटे हुए सहित मिश्रण के लिए यदि अपेक्षित हो, कटे और पालिश किए हुए हीरों के आयात और कटे और पालिश किये हीरों के निर्यात के लिए हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है और इनका एक निर्यात दायित्व होगा।

पात्रता 4क.14.1 कटे और पालिश किए हीरों के निर्यातक जो स्तरकारी हों, को कटे और पालिश किए हीरों के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5 प्रतिशत तक कटे और पालिश किए हीरों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

निर्यात दायित्व 4क.14.2 स्कीम के तहत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 4 के पैराग्राफ 4क के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात 4क.15 वाणिज्य विभाग की अनुमति से नामित एजेंसियों और उनके सहयोगी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की अनुमति से अन्य, विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/भाग लेने के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं तथा ब्राण्डेड आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की अनुमति है। ये निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई शर्तों के अधीन होंगे।

- निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना 4क.16 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा रत्न और आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने- ले जाने की अनुमति होगी।
- आक द्वारा निर्यात 4क.17 विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में (जिसमें विदेशी डाकघर के माध्यम से स्पीड पोस्ट के द्वारा भी निर्यात शामिल है) आभूषण के पार्सल का मूल्य 50,000 अमरीकी डालर तथा भार में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होगा।
- निजी/सार्वजनिक बाँडिड गोदाम 4क.18 कटे और पालिश किए गए हीरों, कटे और पालिश किए गए रंगीन रत्नों, अनकटे और सेट न किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आयात और पुनः निर्यात के लिए एस ई जेड/डी टी ए में 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य सर्वधन की प्राप्ति के अधीन निजी एवं सार्वजनिक बाँडिड गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं।
- हीरा और जवाहरात डॉलर खाते 4क.19 अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकरी और/या हीरे से जड़ित/अजड़ित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्मों तथा कंपनियों जिनका हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार है, के नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपनी व्यापार जारी रख सकती है।

ऐसे खातों में डॉलर बैंक दित और/या निर्यात आय से संपलब्ध होगा और इनका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा -

- (1) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की आयात/खरीद
- (2) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्न और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,
- (3) विदेशी/नामित एजेंसियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर में पुनः भुगतान, और
- (4) निर्यातकों को रुपये लेखा में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता योजना (डी डी ए एस) के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिये गये हैं।

एक गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डालर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रूपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पॉलिश किए

हुए हीरों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति लाइसेंस का हक प्राप्त हो जाएगा।

परिशोधन एवं पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात 4क.20.

(i) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमों के अनुसार घोषणा करने की शर्त पर परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी।

(क) कटे और पालिश किए कीमती और अर्द्धकीमती पत्थरों के परिशोधन के स्वरूप और

(ख) परिशोधन के बाद ऐसे पत्थरों में बदलाव

पुनः आयात की अनुमति उसी पत्तन से दी जायेगी जहाँ से परिशोधन हेतु पत्थरों का निर्यात किया गया था। पुनः आयात के बाद सीमा शुल्क प्राधिकारी निर्यात दस्तावेजों से व्योरो का सत्यापन करेगा। पुनः आयात के लिए अधिकतम 120 दिनों की अवधि अनुमत होगी।

(ii) तथापि, यदि परिशोधित कीमती पत्थर या अर्द्धकीमती पत्थर का उपयोग धरेलु खपत में किया जाना है तो रिपेयर इश्योरेन्स दोनों तरफ के मालभाड़ा में प्रयुक्त भाल की कीमत सहित किए गये रिपेयर की कीमत पर शुल्क के भुगतान पर पुनः आयातित खेप की अनुमति सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(iii) आयातित मद का पुनः निर्यात किया जायेगा।

आभूषणों को गलाने और पुनः निर्यात करने के लिए बहुमूल्य मेटल स्क्रेप/उपयोग किए गए आभूषणों का आयात 4क.21

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गलाने, परिमार्जन और आभूषण के पुनः निर्यात के लिए बहुमूल्य मेटल स्क्रेप/उपयोग किए गए आभूषणों के आयात की अनुमति होगी। तथापि हैण्ड बैगेज के जरिये आयात की अनुमति नहीं होगी।

अस्वीकृत आभूषण का पुनः आयात 4क.22

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 4क.32 के 4क.32.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषण के पुनः आयात की अनुमति होगी।

खेप आधार पर हीरे और आभूषण का निर्यात 4क.23

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे और आभूषण के निर्यात की अनुमति होगी।

अध्याय - पाँच

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम**ई पी. सी. जी स्कीम****5.1**

पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके एक्स के डी/सी के डी समेत) का 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के आधार पर ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए।

कृषि यूनिटों कुटीर अथवा अत्यंत छोटे यूनिटों के मामले में, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात अनुमत होगा बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 12 वर्षों तक आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की गयी हो।

लघु उद्योग एककों हेतु, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक, पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व पूरा करने के अधीन, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात अनुमति दी जाएगी तथा ऐसे आयातों के पश्चात प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश लघु उद्योग एककों के निवेश सीमा से अधिक न हो।

तथापि, 100 करोड़ या इससे अधिक के बचाए गए शुल्क वाले ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में निर्यात दायित्व 12 वर्षों की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा।

यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्वेट न किया गया हो।

पूंजीगत माल में स्पेयर्स, (रीफर्बिस्ट/रीकण्ड्रीशन्ड स्पेयर्स सहित) औजार, जिग्स, फिक्चर, डाइज और माउल्ड्स शामिल होंगे। ईपीसीजी स्कीम के अधीन पुराने पूंजीगत माल का कालावधि पर बिना किसी प्रतिबन्ध के आयात किया जा सकता है।

तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/ बहुदेशीय वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रैवल एजेंटों,

दूर प्रचालकों अथवा दूर परिवहन प्रचालकों और गोल्फ रिजार्ट्स का स्वामित्व रखने वाली/संचालन करने वाली कम्पनियों को निम्नलिखित शर्त के अधीन होगी:-

- (i) होटल, ट्रेवल तथा टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों, जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ अथवा अधिक रूपए हो।
- (ii) मोटरकारों, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात हेतु लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकारों पर 'बचाई शुल्क' राशि विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, ट्रेवल और टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों से औसत विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iii) आयातित वाहनों को सिर्फ पर्यटन हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वाहन के आयात की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

आई टी सी (एच एस) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रतिबन्धित मदों के आयात की अनुमति मुख्यालय स्थित ई एफ सी से अनुमोदन के बाद ईपीसीजी स्कीम के तहत ही दी जाएगी।

5.1क मौजूदा प्लान्ट और मशीनरी के लिए स्पेयर्स (रीफर्बिस्ट/रीकण्डिश्ड स्पेयर्स सहित), औजार, स्पेयर रिफ्रैक्टरीज और उत्प्रेरक के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक की अवधि में निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर हो।

परियोजनाओं के लिए ईपीसीजी

5.1ख स्कीम के तहत परियोजनाओं के आयात हेतु सीमाशुल्क छूट अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01.03.2002 के क्रम. सं. 441 के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजीगत माल के आयात के लिए ई पी जी सी प्राधिकार पत्र भी जारी किया जा सकता है। ऐसे ई पी जी सी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुणा होगा। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा।

खुदरा क्षेत्र हेतु ई पी सी जी

5.1ग खुदरा क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत ढाँचा तैयार करने हेतु खुदरा व्यापारियों को जिनके पास न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ई पी जी सी स्कीम के

तहत रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सकता है। खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्व अर्थात् 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क का 8 गुणा पूरा करना होगा।

पात्रता

5.2

ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं) सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता निर्यातक/विक्रेता(ओं), सहायक विनिर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक और सेवा प्रदायक पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र हैं।

पूंजीगत माल के
आयात की शर्त

5.3

पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

निर्यात दायित्व

5.4

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

- (1) आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं दी गई सेवाओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा। यह औसत पिछले 3 वर्षों के निर्यात निष्पादन का माध्यम होगा।

समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल जिनके पास ई पी सी जी प्राधिकार पत्र है, के निर्यातों द्वारा भी निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकेगा। तथापि, ऐसे मामलों में, अतिरिक्त निर्यात दायित्व पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा किए गए औसत निर्यातों से अधिक होगा, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.7.6 छूट दी गई है।

इसका औसत माल और सेवाओं दोनों के पिछले निर्यात को जोड़कर होगा।

- (2) अग्रिम प्राधिकार पत्र डी एफ आर सी, डी एफ आई ए, डी ई पी भी या ड्रॉबैक योजना के अधीन पोतलदान को ईपीसीजी निर्यात को पूरा करने लिए भी आकलित किया जाएगा।
- (3) निर्यात दायित्व डीटीए को आईटीए-1 की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।
- (4) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे। तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात भी नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त शयल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के संबंध में, पत्तन निर्वहन सेवाओं के लिए रूपए के रूप में प्राप्त भुगतान भी, निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा।

- (5) निर्यात दायित्व (औसत में अधिक) को पूरा करने के मद्दे परिकल्पित विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन देने के उपाय/स्कीमों के तहत प्रोत्साहन/पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

भीआईएफआर यूनिटों
के लिए प्रावधान

5.5.1

बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदनेवाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि भी आई एफ आर के अधीन है, को भी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व बढ़ाने अथवा 12 वर्ष, यदि विनिर्दिष्ट न हो, की अनुमति होगी।

उपरोक्त प्रावधान लघु उद्योग इकाईयों पर भी संबंधित राज्य सरकार की पुनः स्थापना योजना के अनुसार लागू होगी।

एग्रो इकाईयों के
लिए ईपीसीजी

5.5.2

विधिक बचनबद्धता/भांड पत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी (जैसा भी मामला हो) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए दिया जा सकता है जो कि कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाईयों को दिया गया है। बशर्ते कि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पादों(1) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया है।

स्वदेशी रूप से पूंजीगत
माल को प्राप्त करना और
घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.6

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा घरेलू विनिर्माता नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा। ऐसे घरेलू प्राप्ति को ई ओ यू से भी अनुमति दी जाएगी और नीति के पैरा 6.9 (क) में दिए अनुसार उक्त ई ओ यू द्वारा घनात्मक एन एफ ई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को आकलित किया जाएगा।

घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.7

हटा दिया गया है।

निर्यात दायित्व का निर्धारण

5.7क

सीधे आयात के मामले में, निर्यात दायित्व वास्तव में बचाये गये शुल्क के अनुसार होगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में निर्यात दायित्व के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाये गये अनुमानित सीमा शुल्क के अनुसार होगा।

5.8

हटा दिया गया है।

5.9 हटा दिया गया है।

मीजूदा ई पी सी जी
मशीनरी का तकनीकी
उन्नयन

5.10 ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र धारक ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत आयातित मीजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का चुनाव कर सकता है। मीजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन को संचालित करने की शर्त निम्नानुसार है:-

- (1) ईपीसीजी के तहत आयातित मीजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है।
- (2) पुराने पूंजीगत माल के तहत किए गए न्यूनतम निर्यात पहले ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए।
- (3) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि दोनों पूंजीगत माल के लिए निर्धारित कुल निर्यात दायित्व दोनों पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 8 गुणा होगा जिसे नए प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 8 वर्ष में पूरा करना होगा।
- (4) पूंजीगत माल की पुनः स्थापना संचालित करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.20 में दी गई है।
- (5) तकनीकी उन्नयन के लिए सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी और किया जाने वाला न्यूनतम आयात आवेदक फर्म द्वारा प्लॉट और मशीनरी में मीजूदा निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।

फास्ट ट्रैक कम्पनियों
के लिए प्रोत्साहन

5.11 निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ट्रैक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक पूरा कर लिया हो (निर्यातों के औसत स्तर सहित), बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा।

तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

अध्याय - छः

**निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क
(ई एच टी पी) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी)
और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी बी)**

पात्रता

6.1

अपने सारे उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी बी) स्कीम, के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री मेकिंग, री कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती हैं। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

माल का निर्यात
तथा आयात

6.2

(क) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, उपकरण और तकनीकियाँ (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात किया जायेगा बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों। निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोचर/साहित्य पैम्फलेट, होर्डिंग, कैटालॉग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदमों अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हों। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

- (ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी।
- (घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त रूप से छीटीए से आयात प्राप्त कर सकती है। साफ्टवेयर ई ओ यू/डी टी ए यूनिटें साफ्टवेयर के निर्यात की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।
- (ङ.) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियों से भी सोना/चांदी/ प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटें ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज की तारीख से 90 दिन के अन्दर कर देंगी।
- (छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्को रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रूस संघ को निर्यात कर सकती है।
- (ज) स्पेयर्स/उपभोग्यों की खरीद और निर्यातों के 1.5 प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क के बराबर उन्हीं कारशकर्ता/खरीददार निर्यात वस्तुओं के गारंटी अवधि में निर्यात की अनुमति होगी।

पुराना पूंजीगत माल

6.3

पुराना पूंजीगत माल का बिना किसी आयु सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है।

पूंजीगत माल के पट्टे

6.4

पार्टियों के बीच में हुई पक्की संधि के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल उठा सकती है। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत माल, आयात करने/खरीदने

के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

सकल विदेशी मुद्रा
अर्जन(एन एफ ई)

6.5

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 14-1-ग के क्षेत्र विशेष के प्रावधानों को छोड़कर जहाँ उच्च मूल्य सर्वर्धन की जरूरत होगी, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन होंगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संघटित रूप से गिना जाएगा।

अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र
और विधिक बचनबद्धता

6.6

(क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/एल ओ आई का आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी जब से यूनिट ने उत्पादन आरम्भ किया होगा। इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वैधता की अवधि से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छ वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.2 प्रावधानों के संबंध में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्त को अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 और किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड की भागी होगी और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रह अथवा मंसूख हो जाएगा।

(घ) जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपये या न्यूनतम निवेश हो उन पर ई.ओ.यू. के रूप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। यह, हालाँकि, भोजूदा यूनिटों और इ एच टी पी/एसटीपी/बीटीपी, हेण्डीक्राफ्ट/कृषि/पुष्पोत्पादन/जल कृषि/

पशुपालन/सूचना तकनीकी, सेवाएं ब्रास हार्डवेयर, हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

निवेश मानदण्ड

6.7

ई ओ यू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदनों पर

आवेदन और अनुमोदन

(क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंध सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गतिविधियों को छोड़कर) की यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर मंजूरी/नामंजूरी दी जा सकती है।

(ख) अन्य मामलों में, इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

तैयार उत्पाद/

6.8

निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों का सारा उत्पादन निम्निलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा:-

अवशेष/अपशिष्ट/ स्कैप/
शेष और उप-उत्पाद की
घरेलू टैरिफ क्षेत्र
(डी टी ए) में बिक्री

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर यूनिट निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकता है बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की पूर्ति की गई है। डी टी ए बिक्री हकदारी के अन्दर, इकाइयाँ अपने उत्पादों को डी टी ए में यूनिटों द्वारा निर्यातित अथवा निर्यात की संभावना वाले माल जैसे ही बेच सकती है। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इन्स्टैंट टी को छोड़कर) काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों, संगमरमर और समय-समय पर अधिसूचित ऐसी अन्य मदों के रियायती शुल्क पर डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पैकेजिंग/ लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/ कम्पैक्टिंग/ माइक्रोनाइजेशन/ पल्वराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमत के मामले में डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा एकाउण्ट से किया गया हो। डी टी ए को की गई बिक्री भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी।

- (ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी भी रूप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत/अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।
- (ग) रत्न और आभूषण यूनिटों डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया है। सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एजेंसियों से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। (घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रूप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री पर एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त नहीं होगी।
- (ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा। लेकिन ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त छः माह की अवधि और छः माह के भीतर की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है, उसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा मानदण्ड निर्धारित करवाने होंगे। यूनिटों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की

उत्पादों की
उत्पादों के हकदार हैं
उत्पादों के हकदार हैं

प्रतिदिन इस के लिए

अनुमति

पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(म) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की नीति के पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया हो। पैरा 6.8(क) की हकदारी के बाहर उपोत्पाद की बिक्री सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर भी अनुमत होगी।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को तैयार उत्पादनों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए नीति के अधीन पूर्ण शुल्क की अदायगी पर मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है बशर्ते इन यूनिटों ने नीति के अनुसार सकारात्मक निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त किया हो।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी।

(अ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में जहाँ मूलशुल्क और सी वी डी शून्य है, ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा।

(ट) नये ई ओ यू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क बिक्री की अनुमति होगी जो भेषज यूनिटों के अलावा, जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी, के अतिरिक्त पहले वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र
में अन्य आपूर्तियाँ

6.9

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी:-

- (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डी एफ आई ए/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियाँ।
- (ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मदे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।
- (ग) अन्य निर्यातानुमुख ईकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलोजी पार्क/एस ई जेड ईकाई को आपूर्ति ऐसे माल की खरीद के लिए अनुमति नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत की जायेगी।
- (घ) नीति के और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदाम और मुक्त व्यापार तथा गोदाम के क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।
- (ङ) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्ति, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसे मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं।
- (च) निर्यात से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति (सेवा यूनिटों द्वारा) मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए अथवा ऐसी सेवाओं के लिए जिनका अन्वया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान भारतीय रुपये में किया गया हो।
- (छ) सूचना तकनीकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।
- (ज) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैगर्स सहित उपसाधित्रों की आपूर्तियाँ।

अन्यों के माध्यम से निर्यात

6.10

एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विकसित विनिर्मित माल/साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा-6.10 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

डी.टी.ए. से आपूर्तियों
हेतु हकदारी

6.11

(क) निर्यातानुसूच इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों से की गई आपूर्तियों को 'मान्य निर्यात' समझा जाएगा और आपूर्तिकर्ता पर डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात बाधित, यदि कोई हो, के अलावा नीति के अध्याय 8 के अन्वीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसकलेमर प्रस्तुत करने पर नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए जहाँ भी वापसी की सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं है, विकास आयुक्त द्वारा मान्य दरें निर्धारित करवाई जाएंगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मर्दों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इसके अलावा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे-

(1) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति; यथा अधिसूचित, केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी की देश के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(2) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

(3) हटा दिया गया है।

(4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईंधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी दर से लौटा दिया जाएगा।

(5) सेनवैट क्रेडिट पर सेवा शुल्क के भुगतान से छूट

अन्य हकदारियाँ

6.12

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अनुसार आयकर से छूट।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों के विनिर्माण के लिए

औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

- (ग) हटा दिया गया है।
- (घ) निर्यात आय को 12 महीनों के भीतर प्राप्त करना होगा।
- (ङ.) ई ई एफ सी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन की अनुमति होगी।
- (च) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जाब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का (1) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (2) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है और (3) यूनिट का साफ सुथरा ट्रैक रिकार्ड है।
- (छ) एस ई जेड यूनिटों की तरह हो आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी।

अन्तर यूनिट हस्तांतरण

6.13

- (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/ एस ई जेड यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के इन-बॉर्ड-मूवमेंट की प्रक्रिया को अपनाने वाले संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी।

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से ए ई जेड विकासक अथवा यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति भी एस ई जेड अधिनियम 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

- (ख) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी तथा विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिटों को हस्तांतरित या ऋण पर दिया जा सकता है।
- (ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी।

- 6.14 (क)(1) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर डी टी ए में यूनिटों द्वारा फुटकर ठेके के आधार पर माल के रूप और किस्म में परिवर्तन करना भी शामिल है, का डी टी ए में उप ठेके पर उत्पादन प्रक्रिया कर सकती है।
- (2) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक भी उप ठेके पर दे सकते हैं।
- (ख)(1) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी।
- (2) जॉब के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए।
- (3) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं।
- (4) विकास आयुक्त के अनुमोदन से विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उप ठेके की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) जॉब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्कैप/वेस्ट/टुकड़ों को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

- (घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाईयों द्वारा अन्य ई ओ यू/ एस ई जैड/ डीटीए ईकाईयों में उपटेका/ विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।
- प्रयोग न किए गए
माल की बिक्री
- 6.15 क) यदि कोई निर्यातोनमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से प्राप्त किए गये माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो
- (1) यह अन्य ई ओ यू/एसईजैड/ ई एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी इकाईयों को हस्तांतरित कर सकती है या
- (2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात लाइसेंस सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या
- (3) निर्यात कर सकती है। एक ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मर्चों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा।
- (ख) पूंजीगत वस्तुएं और पुराने/अतिरिक्त कल पुर्जों का निर्यात या अन्य ई ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाईयों को हस्तांतरण या लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यहास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोग्य कलपुर्जे विनिर्मित माल, प्रसंसाधित या पैकिंग किया गया और स्कूप/बेस्ट/रिमेनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।
- (ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्त केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।
- (घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी।

- रिकडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना 6.16 निर्यातोन्मुख/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 और नीति के पैराग्राफों 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 व 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।
- आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत 6.17 (क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात से संबंधित नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है।
- (ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।
- ईओयू योजना से बहिर्गमन 6.18 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। उस समय लागू सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान करने पर और बहिर्गमन से संबंधित वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत इस योजना को छोड़ा जा सकता है।
- (ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन के समय उसे जुर्माना देना होगा।
- (ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित एजेंसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मानक शर्तों और उस योजना के अधीन पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले निर्यातानुमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को भुगतान करने पर विकास आयुक्त द्वारा योजना छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट डिबॉर्डिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टि करेंगे। शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात् यूनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी “बेबाकी प्रमाण-पत्र” के आधार पर यूनिट अन्तिम रूप से डिबॉर्डिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबॉर्डिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए “बेबाकी प्रमाण-पत्र” और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिबॉर्डिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

तथापि वे अग्रिम प्राधिकार/डी ई पी बी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं यदि गणना और देय राशि विवादास्पद हैं और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/बैंक गारण्टी के उपलब्ध करवाए जायेंगे।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबॉर्डिंग के

- रिकडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना 6.16 निर्यातोन्मुख/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी चन्मयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 और नीति के पैराग्राफों 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 व 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।
- आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत 6.17 (क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात से संबंधित नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है।
- (ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके हिस्से जो नुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।
- ईओयू योजना से बहिर्गमन 6.18 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती है। उस समय लागू सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान करने पर और बहिर्गमन से संबंधित वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत इस योजना को छोड़ा जा सकता है।
- (ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन के समय उसे जुर्माना देना होगा।
- (ग) रत्न व जैवशत यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित एजेंसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मानक शर्तों और उस योजना के अधीन पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले निर्यातानुसूख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को भुगतान करने पर विकास आयुक्त द्वारा योजना छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट डिबाँडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टि करेंगे। शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात यूनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी “बेबाकी प्रमाण-पत्र” के आधार पर यूनिट अन्तिम रूप से डिबाँडिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबाँडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए “बेबाकी प्रमाण-पत्र” और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिबाँडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

तथापि वे अग्रिम प्राधिकार/डी ई पी बी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं यदि गणना और देय राशि विवादास्पद हैं और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/बैंक गारण्टी के उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबाँडिंग के

पश्चात् डी टी ए में ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ तो जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहाँ डी टी ए यूनिटों के रूप में पूँजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूँजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूँजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

- (छ) एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रूप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अनुसार होगा।

परिवर्तन

6.19

- (क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10(क) और 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

- (ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

एन एफ ई की निगरानी

6.20

- ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से
निर्यात/निर्यात प्रोत्साहन
यात्रा/विदेशी शो रूम के
जरिए निर्यात/शुल्क मुक्त
दुकानें

6.21

- ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें निम्नलिखित के हकदार होंगे:

- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/सामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना।
- (2) स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनियम जेवरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य व्यक्तिगत सामान।
- (3) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए मालों का निर्यात।
- (4) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/ एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना।

वैयक्तिक सामानों का आयात/विदेशी बांड पैसेन्जर सहित निर्यात पार्सल	6.22	रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अधीन किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण ईकाई के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हो।
डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/आयात	6.23	निःशुल्क नमूनों सहित अन्य मालों को सीमा शुल्क नियमों के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाना या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।
ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ	6.24	ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान	6.25	उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है।
ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन	6.26	ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरा के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति के विकास आयुक्त के बजाए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अंतर्मंत्रालय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।
बी टी पी का अनुमोदन	6.27	जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

अध्याय - 7**विशेष आर्थिक जोन**

विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

अध्याय-7क**मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र**

मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र से संबंधित नीति विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

अध्याय - आठ**मान्य निर्यात**

- मान्य निर्यात** 8.1 'मान्य निर्यात' का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए मुग़तान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।
- संभरण की श्रेणियाँ** 8.2 इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का मुख्य / उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को मान्य निर्यात के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :-
- (क) अग्रिम प्राधिकार / वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार/ डी एफ आई ए के प्रति माल का संभरण;
 - (ख) निर्यातोनमुख यूनिटों या सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एटीपी) या इलेक्ट्रॉनिक हार्ड वेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एस टी पी) बायोटेक्नालोजी पार्क (बी टी पी) में स्थित यूनिटों को माल की आपूर्ति।
 - (ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति।
 - (घ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों / निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों / निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहाँ विधिक कशरों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
- इन अभिकरणों / निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथाअधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों / निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है और विदेश में विनिर्मित वस्तुओं के लिए डी डी पी मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित है वस्तुओं और उपस्करों को अधिष्ठापित करने के लिए आपूर्ति (टर्नकी ठेको का एकल उत्तरदायित्व)
- (ङ) पूंजीगत माल की आपूर्ति जिसमें उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु इस पूंजीगत माल के लिए आवश्यक अनअसम्बल/

डिसअसैम्बल्ड हालत में तथा कच्चा माल अर्न्तवर्ती, संघटक, कलपुर्जें शामिल हैं और एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों एवं वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति।

- (घ) शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलू संभरण के लिए माल की आपूर्ति।
- (छ) ऊपर (घ) में शामिल न किए गए पावर प्रोजेक्टों और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति।
- (ज) 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो।
- (झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों द्वारा वित्त पोषित संगठनों को की गई आपूर्ति।
- (ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति।

पैराग्राफ (घ), (ड.), (च) और (छ) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे यदि आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ

8.3

मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे बशर्ते कि यह प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार होगा -

- (क) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार/डी एफ आई ए के प्रति माल की आपूर्ति
- (ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।
- (ग) जहाँ आपूर्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मदे की गई हैं, वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी। अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वापिस किया जाएगा।

आपूर्तिकर्ता को लाभ

8.4.1

- (1) नीति के पैरा 8.2(क) के संबंध में अग्रिम प्राधिकार/डी एफ आई ए के मदे की गई आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता, अन्तर्द्वितीय आपूर्ति हेतु अग्रिम प्राधिकार/डी एफ आई ए का हकदार होगा।

- (2) यदि आपूर्तिकर्ता ने नीति के पैरा 4.1.11 और 4.1.12 की शर्तों के अनुसार अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) या बैंक टू बैंक साख-पत्र के अनुसार आपूर्ति की है तो वह नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) जो कोई भी लागू हो में दिए गए लाभों का हकदार होगा।
- 8.4.2 नीति के पैरा 8.2 (ख) के अनुसार ईओयू/ईएच टीपी/एस टी पी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) जो भी लागू हो में उल्लिखित लाभों का हकदार होगा।
- 8.4.3 नीति के पैरा 8.2 ग के अधीन आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 क) (ख) और (ग) जो भी लागू हो में निर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे।
- 8.4.4 (1) नीति के अन्तर्गत पैरा 8.2 (घ), (च) और (छ) के तहत आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा।
- (2) पैरा 8.2घ में बताये अनुसार केवल ऐसे अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की आपूर्ति, जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित हो, मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगी। ऐसे अभिकरणों / निधियों की सूची परिशिष्ट 13 में दी गई है।
- (3) नीति के पैरा 8.2(च) के तहत मान्य निर्यात के लाभ उन मर्चों पर लागू होंगे, जिनका आयात शून्य सीमाशुल्क पर राजस्व विभाग द्वारा अनुमत होगा बशर्ते कि वह समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 21/2002, दिनांक 1.3.2002 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।
- (4) पैरा-8.2छ के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को की गई पूंजीगत माल और पूंजीगत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक पुर्जों की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभों के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वह स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई पी पी) / इंजीनियरिंग एण्ड, प्रोक्योरमेंट कान्स्ट्रक्ट (ई पी सी) स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गई हो। मान्य निर्यात के लाभ पावर संयंत्रों के नवीकरण / आधुनिकीकरण हेतु भी उपलब्ध होंगे। (आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3क,ख में दिए गए जो भी लागू हों लाभों के लिए पात्र होंगे) तथापि समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व

विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की क्रम सं० 400 में निर्दिष्ट कोई बड़ी पावर परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 8.3 क, ख और ग में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात के लाभ पाने की पात्र होंगी, यदि ऐसी बड़ी योजना

(क) अन्तर्राज्यीय थर्मल पॉवर संयंत्र जिसकी क्षमता 1000 मैगावाट या इससे अधिक है।

(ख) 500 मैगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले एक अन्तर्राज्यीय हाइड्रल पावर प्लान्ट।

(5) नीति के पैराग्राफ 8.2छ के अन्तर्गत उन नई रिफाइनरियों को जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक चलेंगी, को आपूर्ति अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 समय-समय पर यथासंशोधित, की क्रम संख्या 228 में सूची संख्या 17 में विनिर्दिष्ट माल के लिए मान्य निर्यात के लाभ की हकदार होगी। आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों जो भी लागू है, के लिए पात्र होंगे।

8.4.5 नीति के पैरा 8.2(ड.) के तहत की गई आपूर्तियों के मामले में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होगा। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों के पूंजीगत माल और पुर्जों लिए भी उपलब्ध होंगे जिन्हें नौवीं योजना के दौरान स्थापना / दुरुस्त / विस्तार / आधुनीकीकरण किया गया है। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों को की जाने वाली उन आपूर्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो आठवीं/नौवीं योजना में शुरू हुई है और दसवीं योजना तक चलेंगी।

8.4.6 नीति के पैरा 8.2(झ) के अन्तर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होंगी।

8.4.7 नीति के पैरा 8.2 (ञ) के तहत न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट को की गई आपूर्तियों के सम्बन्ध में, नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) जो भी लागू हों, में विनिर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1.3.2002 के अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क की सूची संख्या 43 के क्रम संख्या 401 के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 440 मैगावाट या अधिक हो जिसे आणविक

ऊर्जा विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का अधिकारी न हो, ने प्रमाणित किया हो, की गई आपूर्ति कि मान्य निर्यात लाभ के हकदार होंगी बशर्ते की ऐसी आपूर्तियाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोली (न कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली) प्रक्रिया के अधीन हुई हो।

टर्मिनल उत्पाद शुल्क
वापसी / शुल्क वापसी
के भुगतान से छूट

8.5

माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3(ग) के संबंध में टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट / छूट प्राप्त न किया हो। इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टि / संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद पर नीति के पैरा 8.3(ख) के संबंध में मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि आवेदक द्वारा सेनवेट क्रेडिट सुविधा/छूट प्राप्त न की गई हो। तथापि ऐसी आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए सीमाशुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी।

8.5.1

यथा अधिसूचित उत्पाद शुल्क/शुल्क वापसी को वापिस करने में विलम्ब होने पर ब्याज अदा किया जाएगा।

मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा
की जाने वाली आपूर्तियाँ

8.6.1

मान्य निर्यात के सभी मामलों में आपूर्तियों प्रत्यक्षतः नामित प्रोजेक्ट / एजेंसियों/यूनिटें/अग्रिम प्राधिकार/ई पी सी जी प्राधिकार धारक को की जाएंगी। तथापि, उप ठेकेदार पैरा 8.4 के अनुसार नामित एजेंसियों/प्रोजेक्ट्स के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्तियाँ कर सकता है। उप ठेकेदार तथापि नामित प्रोजेक्टों/एजेंसियों को सीधे आपूर्ति करने के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी आपूर्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-22 ग में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे।

8.6.2

भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकेदारों के भारतीय उप ठेकेदार द्वारा की गयी आपूर्तियाँ भी मान्य निर्यात के लिए पात्र होगी बशर्ते कि करार में मूल रूप में या बाद में उप ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो तथा परिशिष्ट-22ग (खण्ड-1) में निर्धारित प्रपत्र में उपठेकेदार के नाम में परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया हो।

अध्याय - नौ**परिभाषाएं**

- 9.1 विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-
- 9.2 “उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
- 9.3 “अधिनियम” का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट।
- 9.4 “वास्तविक उपयोक्ता” का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।
- 9.5 “वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा फुटकर सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करता है।
- 9.6 “वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:-
1. कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
 2. कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल, या
 3. कोई सेवा उद्योग।
- 9.7 “ए ई जैड” का अर्थ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 8 में महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।
- 9.8 हटा दिया गया है।
- 9.8.1 “अपील” वह आवेदन है जोकि अधिनियम के भाग 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वह आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार

महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में जमा किए जाते हैं।

- 9.9 "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।
- 9.9.1 "प्राधिकार" का अर्थ है विदेश व्यापार नीति की शर्तों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, के भाग 2(छ) में बताया गया है।
- 9.10 "बी ओ ए" का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- 9.11 "बीटीपी" से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नालोजी विभाग की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9.12 "पूँजीगत माल" का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल हैं। पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रारंभिक लाइनिंग हेतु रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलवर पालन, पशु पालन, पृथ्वी कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, भुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- 9.13 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हों।
- 9.14 "संघटक" का अर्थ उप संयोजन या संयोजन का वह पूर्ण जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए। संघटक में उसके सहायक या उपघटकी भी शामिल हैं।
- 9.15 "उपभोज्य" माल का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो।

मर्दे जिनका वास्तविक रूप में पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मर्दे माना जाएगा।

- 9.16 “उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे।
- 9.17 “प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता है। प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।
- 9.18 “विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसे ही अन्य निजी या सरकारी उद्यम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, प्रचार, वित्तीय सहायता प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है। इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।
- 9.19 “विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त।
- 9.20 “डी एफ आर सी” का अर्थ है जारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र
- 9.21 “घरेलू टैरिफ क्षेत्र” का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी से बाहर है।
- 9.22 “शुल्क वापसी” का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आयातित कल-पुर्जे, यदि आपूर्ति की गई है, माल में शामिल है।
- 9.23 “ई. एच. टी. पी.” का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क।

- 9.24 "ई.ओ.यू." का अर्थ है निर्यात उन्मुख एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो।
- 9.25 "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है—कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अधीन हो।
- 9.26 "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27 "निर्यात दायित्व" का अर्थ है:- लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
- 9.27.1 "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है।
- 9.28 "कम्पनी समूह" से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों-
- (त) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदारी होगा, या
 - (त्ते) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो, या
- विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित समूह कम्पनी के लाभ के दावे या गुप के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ के दावों के लिए उनके निर्यात को गणना की जायेगी, समूह कम्पनी नीति की किसी अधिसूचित निर्यात संवर्धन योजना के अधीन आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष पूर्व अद्यस्थित होना चाहिए।
- 9.29 "प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)" का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और "प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)" का नीति के पैरा 2.4 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है।
- 9.30 "आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

- 9.31 “संरचनात्मक सुविधाओं” का अर्थ है औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक संरचना या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो।
- 9.32 “आई टी सी (एच एस)” का अर्थ निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है।
- 9.33 “जाबिंग” का अर्थ है—जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्यवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।
- 9.34 “लाइसेंसिंग प्राधिकारी” का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो अधिनियम/आदेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो।
- 9.35 “लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ उस वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।
- 9.36 “होटल प्रबंधन” से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल शृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल शृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप शामिल किया जायेगा।
- 9.37 “विनिर्माण” का अर्थ है—विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, मरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फर्निशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन रि-इन्जीनियरिंग। विनिर्माण में, इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलधर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, बागवानी, मत्स्य पालन, भुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगुरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।
- 9.38 “विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।
- 9.39 “एम. ए. आई.” का अर्थ बाजार पहुंच पहल स्कीम है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- 9.40 “व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।
- 9.40.1 “ए एल सी” अर्थात् “अग्रिम लाइसेंसिंग समिति” का अर्थ है शुल्क से मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश करने और महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निवेश उत्पादन मूल्य संवर्धन मानदण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति।
- 9.41 एन एफ ई का अर्थ है निवल विदेशी मुद्रा।
- 9.42 “अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
- 9.43 “आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।
- 9.44 “पुर्जो” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो। “पुर्जो” एक संघटक स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है।
- 9.45 “व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कॉर्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।
- 9.46 “नीति” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009।
- 9.47 “निर्धारित” का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश या नीति के तहत निर्धारित से है।
- 9.48 “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है।
- 9.48 “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है।
- 9.49 “कच्ची सामग्री” का अर्थ है:
1. मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो, और

2. किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अभी भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो।
- 9.49.1 क्षेत्रीय अधिकारी का अर्थ है आदेश/अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी।
- 9.50 “पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड/विकास प्राधिकारण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है।
- 9.51 “नियमों” का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम।
- 9.52 “सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है।
- 9.53 “सेवा प्रदान करने वाला” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-
1. भारत से किसी और देश के लिए “सेवा” प्रदान करता है,
 2. भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति करता है, और
 3. भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है।
 4. भारत में निर्यातों से सम्बन्धित सेवा की आपूर्ति जिसका मुग्तान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो या भारतीय मुद्रा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा माना हो।
- 9.54 “एस ई जेड” का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9.55 “जहाज” का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्रतट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं।

ARTSUC

- 9.56 "एस आई ओ एन" का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2002-2007 में अधिसूचित/ अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक विदेश उत्पादन मानदण्डों से है।
- 9.57 "स्पेयर्स" का अर्थ प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है, में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं।
- 9.58 "विनिर्दिष्ट" का अर्थ इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।
- 9.59 "स्तर धारक" का अर्थ उस निर्यातक से है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक या विकास आयुक्त ने पाँच सितारा व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी हो।
- 9.59.1 "भंडार" से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपकरणों का अन्य सामान है चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो।
- 9.60 "एस टी पी" का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है।
- 9.61 "सहायक विनिर्माण" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या उसके हिस्सों/उपांगों/संघटकों का विनिर्माण करता है। सहायक विनिर्माता के साथ-साथ निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 9.62 "तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात" का अर्थ है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक की ओर से किए गए निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख होगा। बी आर सी जी आर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए।
- 9.63 "विनिमय मूल्य" से अभिप्राय है जो कि राजस्व विभाग के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम में बताई गई है।
- 9.64 "यूनिट अनुमोदन समिति" का अर्थ है इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से सम्बन्धित विषयों पर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित समिति।
- 9.65 "वन्य प्राणी" का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड-2(36) में परिभाषित है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION****New Delhi, the 19th April, 2007****No. 1 (RE-2007)/2004—2009**

S.O. 607(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy, 2004—2009 incorporating the Annual Supplement as updated on 19th April, 2007 and contained in Annexure to this notification. The policy shall come into force w.e.f. 1st April, 2007.

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/FTP/AM 08/PC-I]

**B. S. MEENA, Director General of Foreign Trade
and Ex officio Addl. Secy.**

FOREIGN TRADE POLICY

PREAMBLE

CONTEXT

For India to become a major player in world trade, an all encompassing, comprehensive view needs to be taken for the overall development of the country's foreign trade. While increase in exports is of vital importance, we have also to facilitate those imports which are required to stimulate our economy. Coherence and consistency among trade and other economic policies is important for maximizing the contribution of such policies to development. Thus, while incorporating the existing practice of ~~consistency in our~~ Exim Policy, it is necessary to go much beyond and take an integrated approach to the developmental requirements of India's foreign trade. This is the context of the new Foreign Trade Policy.

OBJECTIVES

Trade is not an end in itself, but a means to economic growth and national development. The primary purpose is not the mere earning of foreign exchange, but the stimulation of greater economic activity. The Foreign Trade Policy is rooted in this belief and built around two major objectives. These are:

- (i) To double our percentage share of global merchandise trade within the next five years; and
- (ii) To act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust to employment generation.

STRATEGY

These objectives are proposed to be achieved by adopting, among others, the following strategies:

- (i) Unshackling of controls and creating an atmosphere of trust and transparency to unleash the innate entrepreneurship of our businessmen, industrialists and traders.
- (ii) Simplifying procedures and bringing down transaction costs.
- (iii) Neutralizing incidence of all levies and duties on inputs used in export products, based on the fundamental principle that duties and levies should not be exported.
- (iv) Facilitating development of India as a global hub for manufacturing, trading and services.
- (v) Identifying and nurturing special focus areas which would generate additional

employment opportunities, particularly in semi-urban and rural areas, and developing a series of 'Initiatives' for each of these.

- (vi) Facilitating technological and infrastructural upgradation of all the sectors of the Indian economy, especially through import of capital goods and equipment, thereby increasing value addition and productivity, while attaining internationally accepted standards of quality.
- (vii) Avoiding inverted duty structures and ensuring that our domestic sectors are not disadvantaged in the Free Trade Agreements/Regional Trade Agreements/Preferential Trade Agreements that we enter into in order to enhance our exports.
- (viii) Upgrading our infrastructural network, both physical and virtual, related to the entire Foreign Trade chain, to international standards.
- (ix) Revitalising the Board of Trade by redefining its role, giving it due recognition and inducting experts on Trade Policy.
- (x) Activating our Embassies as key players in our export strategy and linking our Commercial Wings abroad through an electronic platform for real time trade intelligence and enquiry dissemination.

PARTNERSHIP :

The new Policy envisages merchant exporters and manufacturer exporters, business and industry as partners of Government in the achievement of its stated objectives and goals. Prolonged and unnecessary litigation vitiates the premise of partnership. In order to obviate the need for litigation and nurture a constructive and conducive atmosphere, a suitable Grievance Redressal Mechanism will be established which, it is hoped, would substantially reduce litigation and further a relationship of partnership.

The dynamics of a liberalized trading system sometimes results in injury caused to domestic industry on account of dumping. When this happens, effective measures to redress such injury will be taken.

ROADMAP:

This Policy is essentially a roadmap for the development of India's foreign trade. It contains the basic principles and points the direction in which we propose to go. By virtue of its very dynamics, a trade policy cannot be fully comprehensive in all its details. It would naturally require modification from time to time. We propose to do this through continuous updation, based on the inevitable changing dynamics of international trade. It is in partnership with business and industry that we propose to erect milestones on this roadmap.



(KAMAL NATH)
MINISTER FOR COMMERCE & INDUSTRY
GOVERNMENT OF INDIA

NEW DELHI
31ST AUGUST, 2004

GLOSSARY (ACRONYMS)

ACC	Assistant Commissioner of Customs
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayaat Niryaat Form
ARO	Advance Release Order
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BoA	Board of Approval
BoT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Bio Technology Park
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIS	Commonwealth of Independent States
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DoBT	Department of Bio Technology
DC	Development Commissioner
DEPB	Duty Entitlement Pass Book Scheme
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DFRC	Duty Free Replenishment Certificate
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics
DGFT	Director General of Foreign Trade
DIPP	Department of Industrial Policy & Promotion
DoC	Department of Commerce
DoE	Department of Electronics
DoIT	Department of Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Tourism
DTA	Domestic Tariff Area

EDI	Electronic Data Interchange
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EH	Export House
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Process Outsourcing
FDI	Foreign Direct Investment
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FMS	Focus Market Scheme
FOB	Free On Board
FPS	Focus Product Scheme
FT (D&R) Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
GATS	General Agreement on Trade in Services
GRC	Grievance Redressal Committee
HACCP	Hazard Analysis And Critical Control Process
HBP v1	Hand Book of Procedures (Vol. 1)
HBP v2	Hand Book of Procedures (Vol. 2)
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) Classification for Export & Import Items, 2004-2009
ITPO	India Trade Promotion Organisation
LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Under Taking
MAI	Market Access Initiative

MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NOC	No Objection Certificate
PRC	Policy Relaxation Committee
PTH	Premier Trading House
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
REP	Replenishment
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
RSCQC	Regional Sub-Committee on Quality Complaints
S/B	Shipping Bill
SEH	Star Export House
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SFIS	Served from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SION	Standard Input Output Norms
SSI	Small Scale Industry
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STP	Software Technology Park
TÉE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TRQ	Tariff Rate Quota
VA	Value Addition
VKGUY	Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices

CHAPTER 1A**LEGAL FRAMEWORK**

<i>Preamble</i>	1.1	The Preamble spells out the broad framework.
<i>Duration</i>	1.2	This Foreign Trade Policy 2004-2009 (FTP), incorporating provisions relating to export and import of goods and services, shall come into force with effect from 1st April, 2007 and shall remain in force upto 31st March, 2009 unless otherwise specified.
<i>Amendments</i>	1.3	Central Government reserves right in public interest to make any amendments by notification to this Policy in exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act.
<i>Transitional Arrangements</i>	1.4	Authorisations issued before commencement of FTP shall continue to be valid for the purpose and duration for which such Authorisation was issued, unless otherwise stipulated.
	1.5	In case an export or import that is permitted freely under FTP is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that shipment of export or import is made within original validity with respect to available balance and time period of an irrevocable letter of credit established before date of imposition of such restriction. However, a time limit for operationalising such LCs may be prescribed.

CHAPTER 1B

SPECIAL FOCUS INITIATIVES

Special Focus Initiatives

- 1B.1 With a view to doubling our percentage share of global trade within 5 years and expanding employment opportunities, especially in semi urban and rural areas, certain special focus initiatives have been identified for agriculture, handlooms, handicraft, gems & jewellery, leather and Marine sectors.

Government of India shall make concerted efforts to promote exports in these sectors by specific sectoral strategies that shall be notified from time to time.

New Sectoral Initiatives to be announced

Further Sectoral Initiatives in other sectors will also be announced from time to time.

Thrust sectors shall be extended following facilities:

- (i) Agriculture and Village Industry
 - (a) Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana
 - (b) Funds shall be earmarked under ASIDE for development of Agri Export Zones (AEZ)
 - (c) Deleted.
 - (d) Deleted.
 - (e) Capital goods imported under EPCG shall be permitted to be installed anywhere in AEZ.
 - (f) Import of restricted items, such as panels, shall be allowed under various export promotion schemes.
 - (g) Import of inputs such as pesticides shall be permitted under Advance Authorisation for agro exports.
 - (h) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.
- (ii) Handlooms :
 - (a) Specific funds would be earmarked under MAI / MDA Scheme for promoting handloom exports.
 - (b) Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments shall be 5% of FOB value of exports during previous financial year.

- (c) Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples shall be 1% of FOB value of exports during previous financial year.
- (d) Duty free import of old pieces of hand knotted carpets on consignment basis for re-export after repair shall be permitted.
- (e) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.
- (f) Handloom mark enables handloom products to develop a niche market with a distinct identity.
- (g) Machinery and equipment for effluent treatment plants shall be exempt from customs duty.

(iii) Handicrafts:

- (a) New Handicraft SEZs shall be established which would procure products from cottage sector and do finishing for exports.
- (b) Duty free import entitlement of tools, machinery and equipment, trimmings and embellishments shall be 5% of FOB value of exports during previous financial year. Entitlement is broad banded, and shall extend also to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.
- (c) Handicraft EPC is authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable.
- (d) Specific funds would be earmarked under MAI & MDA Schemes for promoting Handicraft exports.
- (e) CVD is exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables.
- (f) New towns of export excellence with a reduced threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.
- (g) Machinery and equipment for effluent treatment plants shall be exempt from customs duty.

(iv) Gems & Jewellery

- (a) Import of gold of 8k and above shall be allowed under replenishment scheme subject to import being accompanied by an Assay Certificate specifying purity, weight and alloy content.
- (b) Duty free import entitlement of consumables, tools, machinery and equipments for metals other than Gold, Platinum shall be 2% and for Gold and Platinum shall be 1% of FOB value of exports during previous financial year. However, for rhodium-plated silver jewellery, entitlement shall be 3%.
- (c) Duty free import entitlement of commercial samples shall be Rs. 300,000.
- (d) Duty free re-import entitlement for rejected jewellery shall be 2% of FOB value of exports.
- (e) Cutting and polishing of gems and jewellery, shall be treated as manufacturing for purposes of exemption under Section 10A of Income Tax Act.

(v) Leather and Footwear

- (a) Duty free import entitlement of specified items shall be 5% of FOB value of exports during preceding financial year.
- (b) Duty free entitlement for import of trimmings, embellishments and footwear components for footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags shall be 3% of FOB value of exports of previous financial year. Such entitlement shall also cover packing material, such as printed and non printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.
- (c) Machinery and equipment for Effluent Treatment Plants shall be exempt from basic customs duty.
- (d) Re-export of unsuitable imported materials such as raw hides & skins and wet blue leathers is permitted.
- (e) CVD is exempted on lining and interlining material notified at S.No 168 of Customs Notification No 21/2002 dated 01.03.2002.
- (f) CVD is exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under Chapter 43 of ITC (HS).

Package for Marine Sector

- (vi) (a) Duty free import of specified specialised inputs / chemicals and flavouring oils is allowed to the extent of 1% of FOB value of preceding financial year's export.
- (b) To allow import of monofilament longline system for tuna fishing at a concessional rate of duty.
- (c) A self removal procedure for clearance of seafood waste is applicable subject to prescribed wastage norms.

Hi-tech products Export Promotion Scheme

- (vii) The scheme has been introduced to promote export of notified hi-tech products.

1B.2 Deleted

CHAPTER-1C**Board of Trade**

Board of Trade (BOT)	1C.1	BOT has a clear and dynamic role in advising government on relevant issues connected with foreign trade.
Terms of Reference	1C.2	<p>BOT has following terms of reference:</p> <ol style="list-style-type: none"> I To advise Government on Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing exports in the light of emerging national and international economic scenarios; II To review export performance of various sectors, identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings; III To examine existing institutional framework for imports and exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve desired objectives; IV To review policy instruments and procedures for imports and exports and suggest steps to rationalize and channelise such schemes for optimum use; V To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade, and to strengthen international competitiveness of Indian goods and services; and VI To commission studies for furtherance of above objectives.
Composition	1C.3	Government shall nominate an eminent person or expert on trade policy to be Chairman of BOT. Government shall also nominate 25 persons, of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, Chairmen of recognized EPCs and President or Secretary-Generals of National Chambers of Commerce will be ex-officio members. BOT will meet at least once every quarter.
	1C.4	Deleted
	Tb	
	1C.6	

CHAPTER-2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

***Exports and Imports
free unless regulated***

2.1 Exports and Imports shall be free, except where regulated by FTP or any other law in force. The item wise export and import policy shall be, as specified in ITC (HS) notified by DGFT, as amended from time to time.

2.1.1 Import / export of arms and related material from / to Iraq shall be prohibited.

2.1.2 Direct or indirect export and import of following items, whether or not originating in Democratic People's Republic of Korea (DPRK), to / from, DPRK is prohibited:

All items, materials equipment, goods and technology including as set out in lists in documents S/2006/814, S/2006/815 and S/2006/853 (United Nations Security Council Documents) which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.

2.1.3 Direct or indirect export and import of all items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water related activities, or to development of nuclear weapon delivery systems, as mentioned below whether or not originating in Iran, to / from Iran is prohibited:

- i) items, listed in INFCIRC/254/Rev8/Part I in document S/2006/814, in Sections B.2 to B.7 as well as A.I and B.I except supply, sale or transfer of equipment covered by B.I when such equipment is for light water reactors and low-enriched uranium covered by A.1.2 when it is incorporated in assembled nuclear fuel elements for such reactors;
- ii) items listed in S/2006/815 except supply sale or transfer of items covered by 19.A.3 of Category II.

Above-mentioned UN Security Council documents are accessible from DGFT web site.

Compliance with Laws

2.2 Every exporter or importer shall comply with the provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there-under, FTP and terms and conditions of any Authorisation granted to him. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. No import or export of rough diamonds shall be permitted unless accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate as specified by Gem & Jewellery EPC (GJEPC).

Interpretation of Policy 2.3

If any question or doubt arises in respect of interpretation of any provision contained in FTP, or classification of any item in ITC (HS) or HBP v1 or HBP v2 or Schedule of DEPB Rates (including content, scope or issue of an authorization there under), said question or doubt shall be referred to DGFT whose decision thereon shall be final and binding.

Procedure 2.4

DGFT may, specify procedure to be followed for an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority, for purpose of implementing provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and FTP. Such procedures shall be published by means of a Public Notice, and may, in like manner, be amended from time to time.

Exemption from Policy / Procedure 2.5

DGFT may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper, on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade.

DGFT may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of FTP or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting committees as under:

Sl. No.	Description	Committee
(i)	Fixation / modification of product norms under all schemes	Norms Committee
(ii)	Nexus with Capital Goods (CG) and benefits under EPCG Schemes	EPCG Committee
(iii)	All other issues	Policy Relaxation Committee (PRC)

Principles of Restriction 2.6

DGFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for:-

- i Protection of public morals.
- ii Protection of human, animal or plant life or health.
- iii Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices.
- iv Prevention of use of prison labour.
- v Protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value.

		vi	Conservation of exhaustible natural resources.
		vii	Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and
		viii	Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.
<i>Restricted Goods</i>	2.7		Any goods, export or import of which is restricted under ITC(HS) may be exported or imported only in accordance with an Authorisation or in terms of a public notice issued in this regard.
<i>Terms and Conditions of a licence / Certificate / Permission / Authorisation</i>	2.8		Every Authorisation shall be valid for prescribed period of validity and shall contain such terms and conditions as may be specified by RA which may include: <ul style="list-style-type: none"> (a) Quantity, description and value of the goods; (b) Actual User condition; (c) Export obligation; (d) Value addition to be achieved; and (e) Minimum export / import price.
<i>Authorisation/Licence/ Certificate/Permission not a Right</i>	2.9		No person may claim an Authorization as a right and DGFT or RA shall have power to refuse to grant or renew the same in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules made there under and FTP.
<i>Penalty</i>	2.10		If an Authorisation holder violates any condition of such Authorisation or fails to fulfill export obligation, he shall be liable for action in accordance with FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under, FTP and any other law for time being in force.
<i>State Trading</i>	2.11		Any goods, import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to STE(s), may be imported or exported by STE(s) as per conditions specified in ITC (HS). DGFT may, however, grant an Authorisation to any other person to import or export any of these goods. <p>Such STE(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale in a non discriminatory manner and shall afford enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.</p>

Importer-Exporter Code (IEC) Number	2.12	No export or import shall be made by any person without an IEC number unless specifically exempted. An IEC number shall be granted on application by competent authority in accordance with procedure specified in HBP v1.
Trade with Neighbouring Countries	2.13	DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.
Transit Facility	2.14	Transit of goods through India from / or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.
Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement	2.15	In case of trade with Russia under Debt Repayment Agreement, DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required, and anything contained in FTP, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.
Actual User Condition	2.16	Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person. However, if such imports require an Authorisation, actual user alone may import such goods unless actual user condition is specifically dispensed with by RA.
Second Hand Goods	2.17	All second hand goods, except second hand capital goods, shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with provisions of FTP, ITC (HS), HBP v1, Public Notice or an Authorisation issued in this regard. Import of second hand capital goods, including refurbished / re-conditioned spares shall be allowed freely. However, second hand personal computers / laptops, photocopier machines, air conditioners, diesel generating sets will only be allowed against a licence. Import of re-manufactured goods shall be allowed only against a licence.
Import of samples	2.18	Import of samples shall be governed by HBP v1.
Import of Gifts	2.19	Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under FTP. In other cases, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from DGFT.

<i>Passenger Baggage</i>	2.20	<p>Bona fide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per limits, terms and conditions thereof in Baggage Rules notified by Ministry of Finance.</p> <p>Samples of such items that are otherwise freely importable under FTP may also be imported as part of passenger baggage without an Authorisation.</p> <p>Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without an Authorisation.</p>
<i>Import on Export basis</i>	2.21	Freely exportable new or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports, jigs, fixtures, dies and moulds may be imported for export without an Authorisation on execution of LUT / BG with Customs Authorities.
<i>Re-import of goods repaired abroad</i>	2.22	Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without an Authorisation.
<i>Import of goods used in projects abroad</i>	2.23	After completion of projects abroad, project contractors may import, without an Authorisation used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.
<i>Sale on High Seas</i>	2.24	Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to FTP or any other law in force.
<i>Import under Lease Financing</i>	2.25	Permission of RA is not required for import of capital goods under lease financing.
<i>Clearance of Goods from Customs</i>	2.26	Goods already imported / shipped / arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against an Authorisation issued subsequently.
<i>Execution of BG/ LUT</i>	2.27	Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, importer shall execute prescribed LUT / BG / Bond with Customs Authority before clearance of goods. In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish LUT / BG / Bond to RA concerned before sourcing material from indigenous supplier / nominated agency as prescribed in HBP vii.

Deleted

Private / Public Bonded Warehouses for Imports	2.28	<p>Private / Public bonded warehouses may be set up in DTA as per terms and conditions of notification issued by DoR.</p> <p>Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such bonded warehouses.</p> <p>Such goods may be cleared for home consumption in accordance with provisions of FTP and against Authorisation, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.</p> <p>If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, importer of such goods shall re-export the goods.</p>
Free Exports	2.29	<p>All goods may be exported without any restriction except to extent such exports are regulated by ITC (HS) or any other provision of FTP or any other law for time being in force.</p> <p>DGFT may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in ITC (HS), may be exported without an Authorisation.</p>
Export of Samples	2.30	Export of samples and Free of charge goods shall be governed by provisions given in HBP v1.
Export of Passenger Baggage	2.31	Bona fide personal baggage may be exported either along with passenger or, if unaccompanied, within one year before or after passenger's departure from India. However, items mentioned as restricted in ITC (HS) shall require an Authorisation.
Export of Gifts	2.32	<p>Goods, including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift.</p> <p>However, items mentioned as restricted for exports in ITC (HS) shall not be exported as a gift, without an Authorisation.</p>
Export of Spares	2.33	Warranty spares (whether indigenous or imported) of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods, (except those restricted under ITC (HS)) may be exported along with main equipment or subsequently but within contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.
Third Party Exports	2.34	Third party exports, as defined in Chapter 9 shall be allowed under FTP.
Export of Imported Goods	2.35	Goods imported, in accordance with FTP, may be exported in same or substantially same form without an Authorisation

provided that item to be imported or exported is not restricted for import or export in ITC (HS).

Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.

	2.36	Goods, including those mentioned as restricted for import (except prohibited items) may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without an Authorisation provided that item is freely exportable without any conditionality / requirement of Licence / permission as may be required under ITC (HS) Schedule II.
Export of Replacement Goods	2.37	Goods or parts thereof on being exported and found defective / damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by Customs authorities provided that replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC (HS).
Export of Repaired Goods	2.38	<p>Goods or parts, except restricted under ITC (HS), thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export.</p> <p>Such goods shall be allowed clearance without an Authorisation and in accordance with customs notification.</p>
Private Bonded Warehouses for Exports	2.39	<p>Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per terms and conditions of notifications issued by DoR.</p> <p>Such warehouses shall be entitled to procure goods from domestic manufacturers without payment of duty. Supplies made by a domestic supplier to such notified warehouses shall be treated as physical exports provided payments are made in free foreign exchange.</p>
Denomination of Export Contracts	2.40	<p>All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but export proceeds shall be realised in freely convertible currency.</p> <p>However export proceeds against specific exports may also be realized in rupees provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of ACU or Nepal or Bhutan. Additionally, rupee payment through Vostro account must be against payment in free foreign currency by buyer in his non-resident bank account. Free foreign exchange remitted by buyer to his non-resident bank (after deducting the bank service charges) on</p>

account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes of FTP.

Contracts [for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU)] shall be denominated in ACU Dollar. Central Government may relax provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and Invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank / Government of India line of credit.

Realisation of Export Proceeds	2.41	If an exporter fails to realise export proceeds within time specified by RBI, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law in force, be liable to action in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under and FTP.
Free movement of export goods	2.42	Consignments of items meant for exports shall not be withheld /delayed for any reason by any agency of Central / State Government. In case of any doubt, authorities concerned may ask for an undertaking from exporter.
No seizure of Stock.	2.42.1	No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports. In exceptional cases, concerned agency may seize the stock on basis of prima facie evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.
Export Promotion Councils	2.43	Basic objective of Export Promotion Councils (EPCs) is to promote and develop Indian exports. Each Council is responsible for promotion of a particular group of products, projects and services as given in HBP v1.
Registration -cum- Membership Certificate (RCMC)	2.44	Any person, applying for: (i) an Authorisation to import / export, [except items listed as restricted items in ITC(HS)] or (ii) any other benefit or concession under FTP shall be required to furnish RCMC granted by competent authority in accordance with procedure specified in HBP v1 unless specifically exempted under FTP.
	2.45	Deleted
Trade Facilitation through EDI Initiatives	2.45.1	It is endeavor of Government to work towards greater simplification, standardization and harmonization of trade documents using international best practices. As a step in this direction, DGFT shall move towards an automated environment for electronic filing, retrieval and authentication of documents based on agreed protocols and message exchange with other community partners including Customs and Banks.

DGCI&S Commercial Trade Data	2.45.2	To enable users to make commercial decisions in a professional manner, DGCI&S trade data shall be made available with a minimum time lag in a query based structured format on a commercial criteria.
Fiscal Incentives to promote EDI Initiatives adoption	2.45.3	With a view to promote the use of Information Technology, DGFT will provide fiscal incentives to user community. Deductions in Application Fee would be admissible for applications signed digitally or / and where application fee is paid electronically through EFT (Electronic Fund Transfer). Details are enumerated in HBP v1.
Regularization of EO default and settlement of customs duty and interest through Settlement Commission	2.46	With a view to providing assistance to firms who have defaulted under FTP for reasons beyond their control as also facilitating merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower Settlement Commission in CBEC to decide such cases also with effect from 01.04.2005.
Easing Of Documentation Requirement	2.47	Pending finalisation of Single Common Document (SCD) for international trade, Government Departments dealing with exports and imports will honour Authorisation issued by other Government departments based on verification of export documents Like shipping bill, bank realization certificate, Packing list, bill of lading etc. and will not insist upon fresh submission of these documents.
Exemption / Remission of Service Tax in DTA	2.48.1	For all goods and services which are exported from units in DTA and units in EOU / BHTP / STP / BTP exemption / remission of service tax levied and related to exports, shall be allowed, as per prescribed procedure in Chapter 4 of HBP v1.
Exemption from Service Tax in SEZ	2.48.2	Units in SEZ shall be exempted from service tax.
Exemption from Service Tax on Services received abroad	2.48.3	For all goods and services exported from India, services received / rendered abroad, where ever possible, shall be exempted from service tax.

GRIEVANCE REDRESSAL

DGFT as a facilitator of exports/ imports	2.49	DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Focus is on good governance, which depends on clean, transparent and accountable delivery systems.
Citizen's Charter	2.49.1	DGFT has in place a Citizen's Charter, giving time schedules for providing services to clients, and details of grievance committees at different levels.

<i>Grievance Redressal Mechanism</i>	2.49.2	<p>In order to facilitate speedy redressal of grievances of trade and industry, a new grievance redressal mechanism has been put in place in the form of GRC by a Government Resolution.</p> <p>Government is committed to resolving all outstanding problems and disputes pertaining to past policy periods through GRC set up on 27.10.2004, for condoning delays, regularizing breaches by exporters in bonafide cases, resolving disputes over entitlements, granting extensions for utilization of Authorisations.</p>
	2.49.3	Deleted
<i>Force Majeure Clause</i>	2.50	<p>Export Obligation period and validity of an authorization shall be extended for a further appropriate period to be notified by DGFT, from date of expiry of its validity in case unit / firm / company suffers on account of unforeseen circumstances / reasons and force majeure.</p>

CHAPTER-3

PROMOTIONAL MEASURES

***Assistance to
States for
Infrastructure
Development of
Exports (ASIDE)***

- 3.1 Scheme for Assistance to States for Infrastructure Development of Exports (ASIDE) is formulated to encourage State Governments to participate in promoting exports, and is administered by Department of Commerce (DoC).

Objectives of ASIDE include:

- (i) Developing infrastructure such as roads connecting production centers with ports,
- (ii) Setting up of Inland Container Depots (ICD) and Container Freight Stations (CFS),
- (iii) Creation of new State level export promotion industrial parks / zones,
- (iv) Augmenting common facilities in existing zones,
- (v) Equity participation in infrastructure projects,
- (vi) Development of minor ports and jetties,
- (vii) Assistance in setting up of common effluent treatment facilities,
- (viii) Stabilizing power supply, and
- (ix) Any other activity as may be notified by DoC.

Details of ASIDE are available at <http://commerce.nic.in>

***Market Access
Initiative (MAI)***

- 3.2 MAI scheme, intended to provide financial assistance for medium term export promotion efforts with sharp focus on a country / product, is administered by DoC.

Financial assistance is available for Export Promotion Councils (EPCs), Industry and Trade Associations (ITAs), Agencies of State Governments, Indian Commercial Missions (ICMs) abroad and other eligible entities as may be notified.

A whole range of activities can be funded under MAI scheme. These include, amongst others,

- (i) Market studies.

- (ii) Setting up of showroom / warehouse,
- (iii) Sales promotion campaigns,
- (iv) International departmental stores,
- (v) Publicity campaigns,
- (vi) Participation in international trade fairs,
- (vii) Brand promotion,
- (viii) Registration charges for pharmaceuticals, and
- (ix) Testing charges for engineering products.

Each of these export promotion activities can receive financial assistance from Government ranging from 25% to 100% of total cost depending upon activity and implementing agency. Full text of guidelines is available at <http://commerce.nic.in>.

**Marketing
Development
Assistance (MDA)**

- 3.2.1 MDA Scheme is intended to provide financial assistance for a range of export promotion activities implemented by EPCs, ITAs on a regular basis every year. The scheme is administered by DoC.

Assistance includes, amongst others, participation in

- (i) Trade Fairs and Buyer Seller meets abroad or in India, and
- (ii) Export promotion seminars.

Financial assistance with travel grant is available to exporters traveling to Latin America, Africa, CIS region, ASEAN countries, Australia and New Zealand. In other areas, financial assistance without travel grant is available.

MDA assistance is available for exporters with annual export turnover upto Rs 10 Crores. Full text of guidelines is available at <http://commerce.nic.in>.

**Meeting Legal
expenses for
Trade related
matters**

- 3.2.1.1 DOC would provide financial assistance to deserving exporters on recommendation of EPCs for meeting cost of legal expenses for trade related matters.

**Towns of Export
Excellence (TEE)**

- 3.3 A number of towns have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximizing their potential and enabling them to move higher in value chain and tap new markets.

Selected towns producing goods of Rs. 1000 crore or more will be notified as TEE based on potential for growth in exports. However for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, threshold limit would be Rs 250 crores.

Recognized associations of units will be able to access funds under MAI scheme for creating focused technological services. Common service providers in these areas shall be entitled for EPCG scheme. Further such areas will receive priority for assistance under ASIDE scheme.

Notified TEE are listed in Appendix 7 of HBP v1.

***Brand Promotion
and Quality***

- 3.4.1 Central Government aims to encourage manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. Central Government will extend support and assistance to Trade and Industry to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote total quality management.

Test Houses

- 3.4.2 Central Government will assist in modernisation and upgradation of test houses and laboratories to bring them at par with international standards.

***Quality Complaints /
Disputes***

- 3.4.3 Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at Regional Offices of this Directorate shall investigate quality complaints received from foreign buyers. Guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, are given in Appendix-16 of HBP v1.

***Trade disputes
affecting trade relations***

- 3.4.4 If it comes to DGFT notice or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner that

- (i) is gravely prejudicial to trade relations of India with any other country; and / or
- (ii) is gravely prejudicial to interest of other persons engaged in exports or imports; and / or
- (iii) has brought disrepute to the country;

DGFT may take action against such exporter or importer in accordance with FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and FTP.

3.5 **EXPORT AND TRADING HOUSES.**

***Export and Trading
Houses***

- 3.5.1 Merchant as well as Manufacturer Exporters, Service Providers, Export Oriented Units (EOUs) and Units located in Special Economic Zones (SEZs), Agri Export Zones (AEZs), Electronic

Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs) shall be eligible for status.

Status Category

3.5.2

Applicant shall be categorized depending on his total FOB (FOR - for deemed exports) export performance during current plus previous three years (taken together) upon exceeding limit below. For Export House (EH) Status, export performance is necessary in at least two out of four years (i.e., current plus previous three years).

Status Category**Export Performance
FOB / FOR Value
(Rupees in Crores)**

Export House (EH)	20
Star Export House (SEH)	100
Trading House (TH)	500
Star Trading House (STH)	2500
Premier Trading House (PTH)	10000

Note

1. Exporters in Small Scale Industry (SSI) / Tiny Sector / Cottage Sector, Units registered with KVICs / KVIBs, Units located in North Eastern States, Sikkim and Jammu & Kashmir, Units exporting handloom / handicrafts / hand knotted or silk carpets, exporters exporting to countries in Latin America / CIS / sub-Saharan Africa as listed in Appendix-9, Units having ISO 9000 (series) / ISO 14000 (series) / WHOGMP / HACCP / SEI CMM level-II and above status granted by agencies listed in Appendix-6 of HBP v1, exports of services and exports of agro products shall be entitled for double weightage on exports made for grant of status. Double Weightage shall be admissible to Merchant as well as Manufacturer Exporters. However, a shipment can get double weightage only once in any one of above categories.
- 1(a) Transfer of export performance from one to another is not permitted. Therefore disclaimer system shall not be allowed for counting of export turnover.
2. Exports made on re-export basis shall not be counted for recognition.
3. Exports made by subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of limited company

for recognition only if limited company has a majority share holding in subsidiary company.

4. Deleted

Privileges

3.5.2.1 A Status Holder shall be eligible for following facilities:

- i) Authorisation and Customs clearances for both imports and exports on self-declaration basis;
- ii) Fixation of Input-Output norms on priority within 60 days;
- iii) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. Remittance / Receipts, however, would be received through banking channels;
- iv) 100% retention of foreign exchange in EEFC account;
- v) Enhancement in normal repatriation period from 180 days to 360 days;
- vi) Deleted
- vii) Exemption from furnishing of BG in Schemes under FTP; and
- viii) SEHs and above shall be permitted to establish Export Warehouses, as per DoR guidelines

3.5.3 Deleted

3.6 **SERVICES EXPORTS**

Services Exports

3.6.1 Services include all 161 tradable services covered under GATS where payment for such services is received in free foreign exchange. A list of services is given in Appendix 10 of HBP v1.

Registration cum Membership Certificate (RCMC) for Service Providers

3.6.2 Software exporters shall register themselves with Electronics and Software EPC. Exporters of 13 specific services listed in Sl. No. 34 of Appendix 2 of HBP v1 are required to register themselves with Services EPC. Other service exporters shall register themselves with Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO).

Common Facility Centres

3.6.3 Government shall promote establishment of Common Facility Centres for use by home-based service providers, particularly in areas like Engineering & Architectural design, Multi-media operations, Software developers etc., in State and District-level towns, to draw in a vast multitude of home-based professionals into services export arena.

3.6.4 SERVED FROM INDIA SCHEME (SFIS)

- Objective** 3.6.4.1 Objective is to accelerate growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served From India' brand, instantly recognized and respected world over.
- Eligibility** 3.6.4.2 All Service Providers, of services listed in Appendix 10 of HBP v1, who have a total free foreign exchange earning of at least Rs. 10 Lakhs in preceding financial year shall qualify for Duty Credit scrip. For Individual Service Providers, minimum would be Rs 5 Lakhs.
- Entitlement** 3.6.4.3 All Service Providers (except Hotels, Restaurants and other Service Providers in Tourism Sector) shall be entitled to Duty Credit scrip equivalent to 10% of free foreign exchange earned during preceding financial year.
- However services and service providers as listed in Paragraph 3.18.1 of HBP v1 shall not be entitled.
- Remittances** 3.6.4.3.1 Free foreign exchange earned through International Credit Cards and other instruments as permitted by RBI for rendering of service shall also be taken into account for Duty Credit scrip.
- Hotels, Restaurants & Other Service Providers in Tourism Sector** 3.6.4.4 Hotels of one-star and above (including managed hotels) and heritage hotels approved by DoT and other Service providers in tourism sector registered with DoT shall be entitled to duty credit scrip equivalent to 5% of free foreign exchange earned during preceding financial year.
- Stand-alone restaurants will be entitled to duty credit equivalent to 10% of foreign exchange earned by them in preceding financial year.
- Imports allowed** 3.6.4.5 Duty Credit scrip may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables; that are otherwise freely importable under ITC (HS). Imports shall relate to any service sector business of applicant.
- Utilization of Duty Credit scrip earned shall not be permitted for payment of duty in case of import of vehicles, even if such vehicles are freely importable under ITC (HS).
- In case of hotels, golf resorts and stand-alone restaurants having catering facilities, Duty Credit scrip may also be used for import of consumables including food items and alcoholic beverages.

Non Transferability	3.6.4.6 Entitlement / goods (imported / procured) shall be non transferable (except within group company and managed hotels) and be subject to Actual User condition.
	3.6.4.7 Deleted to 3.6.4.9
Procurement from Domestic Sources	3.6.4.10 Utilization of Duty Credit Scrip shall be permitted for payment of excise duty in terms of DoR notification issued for procurement from domestic sources, of items permitted under Para 3.6.4.5.
	3.7 Deleted
	3.8 VISHESH KRISHI AND GRAM UDYOG YOJANA (VKGUY) (SPECIAL AGRICULTURE AND VILLAGE INDUSTRY SCHEME)
Objective	3.8.1 Objective of VKGUY is to promote exports of <ul style="list-style-type: none"> (i) Agricultural Produce and their value added products; (ii) Minor Forest Produce and their value added variants; for exports w.e.f 1.4.2004 (iii) Gram Udyog Products, for exports w.e.f 01.04.2006; and (iv) Forest Based Products, for exports w.e.f 01.04.2007. <p>Such products shall be listed in Appendix 37A of HBP v1.</p>
Entitlement	3.8.2 Duty Credit scrip benefits are granted with an aim to compensate high transport costs. Exporters, of products notified in Appendix 37A of HBP v1, shall be entitled for Duty Credit scrip equivalent to 5% of FOB value of exports (realized in free foreign exchange). <p>However, Duty Credit scrip benefits shall be granted only at a reduced rate of 3.5% of FOB value of exports (realized in free foreign exchange) in such cases where exporter has availed benefits under Chapter 4 of FTP for import of Agriculture Inputs (other than catalysts, consumables and packing materials) relating to export item under this scheme.</p> <p>Period of exports for which entitlement is granted is given in Appendix 37A of HBP v1.</p>

However, additional products notified / clarified in Appendix 37A of HBP v1 shall be entitled for Duty Credit Scrip on exports, w.e.f 1.4.2007, unless otherwise specified.

3.8.2.1 Exports made by EOUs / BTPs who do not avail direct tax benefits / exemption shall be eligible, provided the same is not covered under Paragraph 3.8.2.2.

3.8.2.2 Following exports shall not be taken into account for Duty Credit scrip entitlement.

- (a) (i) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP;
- (ii) Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transshipped through India;
- (b) Deemed Exports;
- (c) Exports made by SEZ units; and
- (d) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).

3.8.3 Deleted

to

3.8.5

3.8.6 All Status Holders shall be incentivised with duty credit script equal to 10% of FOB value of agricultural exports which can be used for duty free import / procurement of capital goods related to infrastructure meant for agro-processing to promote agricultural exports. This would be in addition to prevailing benefits in other schemes administered by Ministry of Agriculture and others for infrastructure development for agriculture, agricultural items and agro-processing activities like:-

- (i) Cold storage units including Controlled Atmosphere (CA) and Modified Atmosphere (MA) Stores, pre-cooling Units and mother storage for onions etc.
- (ii) Pack Houses (including facilities for handling, grading, sorting and packaging etc.), and
- (iii) Reefer Van / Containers.

Assessment of applicant's proposal would be done with respect to past export performance and on a first come first served basis.

3.9 FOCUS MARKET SCHEME (FMS)**Objective**

- 3.9.1 Objective is to offset high freight cost and other externalities to select international markets with a view to enhance our export competitiveness in these countries.

Entitlement

- 3.9.2 Exporters of all products through EDI enabled ports to notified countries (as in Appendix 37C of HBP v1) shall be entitled for Duty Credit scrip equivalent to 2.5% of FOB value of exports for each licensing year commencing from 1st April, 2006.

However additional Markets notified in Appendix 37C of HBP v1 shall be entitled for Duty Credit scrip on exports w.e.f 1.4.2007.

- 3.9.2.1 Exports made by EOUs / EHTPs / BTPs who do not avail direct tax benefits / exemption shall be eligible, provided the same is not covered under Paragraph 3.9.2.2.
- 3.9.2.2 Following exports shall not be taken into account for computation of entitlement:
- a. (i) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP;
 - (ii) Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India;
 - b. Export turnover of SEZ units or supplies made to such units or SEZ products exported through DTA units;
 - c. Deemed Exports;
 - d. Service Exports;
 - e. Diamonds and other precious, semi precious stones;
 - f. Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded Jewellery;
 - g. Ores and Concentrates, of all types and in all forms;
 - h. Cereals, of all types;
 - i. Sugar, of all types and in all forms;
 - j. Crude / Petroleum Oil & Crude / Petroleum based Products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms; and
 - k. Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).

	3.9.2.3	Deleted
	3.9.3 to 3.9.6	Deleted
	3.10	FOCUS PRODUCT SCHEME (FPS)
Objective	3.10.1	Objective is to incentivise export of such products, which have high employment intensity in rural and semi urban areas, so as to offset infrastructure inefficiencies and other associated costs involved in marketing of these products.
Entitlement	3.10.2	Exports of notified products (as in Appendix 37D of HBP v1) through EDI enabled ports to all countries shall be entitled for Duty Credit scrip equivalent to 1.25% of FOB value of exports for each licensing year commencing from 1 st April, 2006. However, additional products notified / clarified in Appendix 37D of HBP v1 shall be entitled for Duty Credit scrip on exports w.e.f 1.4.2007.
	3.10.2.1	Exports made by EOUs / EHTPs / BTPs who do not avail direct tax benefits / exemption shall be eligible, provided the same is not covered under Paragraph 3.10.2.2.
	3.10.2.2	Following exports shall not be taken into account for computation of entitlement. <ol style="list-style-type: none"> a. (i) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP; (ii) Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India; b. Export turnover of SEZ units or supplies made to such units or SEZ products exported through DTA units; and c. Deemed Exports.
	3.10.2.3	Deleted
	3.10.3 to 3.10.6	Deleted
	3.11	HIGH-TECH PRODUCTS EXPORT PROMOTION SCHEME
Objective	3.11.1	Objective is to incentivise export of High Technology products.
Entitlement	3.11.2	Exports of notified High Tech products (as notified in Appendix 37E of HBP v1) through EDI enabled ports to all countries,

shall be entitled for Duty Credit scrip equivalent to 10 % of incremental growth in exports of notified products put together (realized in free foreign exchange) for current year (i.e., 2007-08) over previous year (i.e., 2006-07) for each licensing year commencing from 1st April, 2007.

Computation would be on following basis :

- (i) Exports of notified products taken together.
- (ii) FOB value realized (as reflected in BRC / FIRC).
- (iii) Applicant with 'nil' exports in base year shall not be eligible.



Ceiling

3.11.3 Duty Credit Scrip shall not exceed Rs 15 Cr for an exporter for all shipments done in a licensing year put together, for which benefit is being claimed under this scheme.

Ineligible Exports / Categories

3.11.4 Following shall not be counted for entitlement

- (i) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP;
- (ii) Exports originating in third country but transshipped through India;
- (iii) Exports of SEZ units or SEZ products exported through DTA units; and
- (iv) Deemed Exports.

3.12 COMMON PROVISIONS FOR SCHEMES UNDER THIS CHAPTER, EXCEPT WHERE SPECIFICALLY PROVIDED FOR.

CENVAT / Drawback

3.12.1 Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Duty Credit scrip shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per DoR rules, except under SFIS.

Special Provisions

3.12.2 Government reserves right in public interest, to specify export products or services or exports to such countries, which shall not be eligible for computation of entitlement.

Further Government reserves right to change ceiling on Duty Credit scrip under this chapter.

Similarly, Government may also notify goods (in Appendix 37B of HBP v1), which shall not be allowed for import under Duty Credit scrips.

<i>TRA Facility</i>	3.12.3	Utilization of Duty Credit Scrip for imports from a port other than port of registration shall be allowed under Telegraphic Release Advice (TRA) facility as per DoR notification.
<i>Imports Allowed</i>	3.12.4	Duty Credit Scrip may be used for import of inputs or goods including capital goods, provided same is freely importable under ITC (HS). However, import of items listed in Appendix 37B of HBP v1 shall not be permitted to be debited.
<i>Free Transferability</i>	3.12.5	Duty Credit scrip and items imported against it would be freely transferable, except under SFIS.
<i>Exclusivity of Entitlement</i>	3.12.6	For a shipment, benefit under any one of schemes covered in this Chapter can alone be claimed, at exporter's option.
<i>Import under Lease financing</i>	3.12.7	Utilization of Duty Credit scrip shall be permitted for payment of duty in case of import of capital goods under lease financing in terms of provision in Para 2.25 of FTP.
<i>Transfer of Export Performance</i>	3.12.8	Transfer of export performance from one to another shall not be permitted. Thus, a shipment bill containing name of applicant shall be counted in export performance / turnover of applicant only if export proceeds from overseas are realized in applicant's bank account and this shall be evidenced from BRC / FIRC.

CHAPTER-4

DUTY EXEMPTION & REMISSION SCHEMES

***Duty Exemption
and Remission Schemes***

4.1

Duty exemption schemes enable duty free import of inputs required for export production. Duty Exemption Schemes consist of (a) Advance Authorisation and (b) Duty Free Import Authorisation (DFIA). A Duty Remission Scheme enables post export replenishment / remission of duty on inputs used in export product. Duty remission schemes consist of (a) Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) and (b) Duty Drawback (DBK) Scheme.

***Re-import of exported
goods under Duty
Exemption / Remission Scheme***

4.1.1

Goods exported under Advance Authorisation / DFIA / DEPB may be re-imported in the same or substantially same form subject to DoR specified conditions.

Value Addition

4.1.2

Value addition (VA) for the purpose of this Chapter (Except for Gems and Jewellery Sector) shall be:-

$$VA = \frac{A - B}{B} \times 100, \quad \text{where}$$

A FOB value of export realised / FOR value of supply received.

B CIF value of inputs covered by authorisation, plus any other imported materials used on which benefit of DBK is claimed.

ADVANCE AUTHORISATION SCHEME

Advance Authorisation

4.1.3

An Advance Authorisation is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts which are consumed / utilised to obtain export product, may also be allowed. DGFT, by means of Public Notice, may exclude any product(s) from purview of Advance Authorisation.

Duty free import of mandatory spares upto 10% of CIF value of Authorisation which are required to be exported / supplied with resultant product are allowed under Advance Authorisation.

Advance Authorisations are issued for inputs and export items given under SION. These can also be issued on the basis of

Adhoc norms or self declared norms as per para 4.7 of HBP v1.

Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) for:

- i) Physical exports (including exports to SEZ); and / or
- ii) Intermediate supplies; and /or
- iii) supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of FTP;
- iv) supply of 'stores' on board of foreign going vessel / aircraft subject to condition that there is specific SION in respect of item(s) supplied.

In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of FTP, an Advance Authorisation can also be availed by sub-contractor to such project provided name of sub contractor(s) appears in main contract.

Such Authorisation can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.

4.1.4 Advance Authorisations are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any. However, imports for supplies covered under paragraph 8.2 (h) & (i) will not be exempted from payment of applicable anti-dumping and safeguard duty, if any.

4.1.5 Advance Authorisation and / or materials imported thereunder will be with actual user condition. It will not be transferable even after completion of export obligation. However, Authorisation holder will have option to dispose off product manufactured out of duty free inputs once export obligation is completed.

4.1.6 Advance Authorisations necessitate exports with a positive value addition. Exports to SEZ Units / supplies to Developers / Co-developers, irrespective of currency of realization, would also cover.

For physical exports for which payments are not received in freely convertible currency, same shall be subject to value addition as specified in Appendix 11 of HBP v1.

In case of Authorisation for import of Tea, minimum value addition under Advance Authorisation shall be 100%.

Similarly, in case of spices {covered by Chapter 9 of ITC(HS)}, duty free import of spices shall be permitted only for value addition purposes like crushing/ grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc. and minimum value addition shall be 15%.

- 4.1.7 Advance Authorisation shall be issued in accordance with Policy and procedure in force on Authorisation issue date.

Validity period of Advance Authorisation for import shall be as prescribed in HBP v1.

***Free of Cost Supply
by Foreign Buyer***

- 4.1.8 Facility of Advance Authorisation shall also be available where some or all inputs are supplied free of cost to exporter by foreign buyer.

In such cases, for calculation of VA, notional value of free of cost inputs along with value of other duty-free inputs shall be taken into consideration. However, if all inputs are supplied free of cost, exporter shall also have option to follow provision prescribed by DoR.

Export Obligation

- 4.1.9 Period for fulfillment of export obligation under Advance Authorisation shall be as prescribed in HBP v1.

***Provision for BIFR
units***

- 4.1.9 A Any firm / company registered with BIFR or any firm / company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed Export Obligation Period (EOP) extension as per rehabilitation package prepared subject to approval of BIFR or 5 years if not specified, without payment of composition fee.

Above provisions apply also to SSI units as per rehabilitation scheme of concerned State government.

***Advance Authorisation
for Annual Requirement***

- 4.1.10 Advance Authorisation can also be issued for annual requirement.

Status Certificate holder and all other categories of exporters having past export performance (in preceding two years) shall be entitled for Advance Authorisation for annual requirement.

Entitlement in terms of CIF value of imports shall be upto 300% of FOB value of physical export and / or FOR value of deemed export in preceding licensing year or Rs 1 crore, whichever is higher.

**Advance Release Orders
(ARO) and Invalidation
Letter**

4.1.11 Holder of Advance Authorisation, Advance Authorisation for annual requirement, Diamond Imprest Authorisation and Duty Free Import Authorisation intending to source inputs from indigenous sources / State Trading Enterprises in lieu of direct import has option to source them either against Advance Release Order (ARO) or Invalidation letter denominated in free foreign exchange / Indian rupees. However, supplies may be obtained against Authorisation from EOU / EHTP / BTP / STP / SEZ units, without conversion into ARO or Invalidation letter.

Transferee of DFIA shall also be eligible for ARO / invalidation letter facility.

Validity period of ARO shall be as prescribed in HBP v1.

**Back-to-Back
Inland Letter of Credit**

4.1.12 Holder of Advance Authorisation, Advance Authorisation for annual requirement, DFIA and Diamond Imprest Authorisation may, instead of applying for an ARO or Invalidation letter, avail of the facility of back-to-back Inland Letter of Credit in accordance with procedure specified in HBP v1.

Prohibited Items

4.1.13 Prohibited items of imports mentioned in ITC(HS) shall not be imported under Advance Authorisation / DFIA. Further items reserved for imports by STEs cannot be imported against Advance Authorisation / DFIA. However those items can be procured from STEs against ARO or Invalidation letter.

STEs are also allowed to sell goods on High Sea Sale basis to holders of Advance Authorisation / DFIA holder.

In addition, STEs are permitted to issue "No Objection Certificate (NOC)" for import by advance Authorisation / DFIA holder. Authorisation Holder would be required to file Quarterly Returns of imports effected against such NOC to concerned STE and STE would submit half-yearly import figures of such imports to concerned administrative Department for monitoring with a copy endorsed to DGFT.

Similarly prohibited items of exports mentioned in ITC(HS) shall not be exported under Advance Authorisation / DFIA scheme. Export of restricted items shall be subject to all conditionalities or requirements of export Authorisation or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS).

Admissibility of Drawback

4.1.14 In case of an Advance Authorisation, drawback shall be available for any duty paid material, whether imported or indigenous, used in goods exported, as per drawback rate fixed by DoR, Ministry of Finance (Directorate of Drawback). Drawback allowed shall be mentioned in Authorisation.

DUTY FREE REPLENISHMENT CERTIFICATE

4.2 Deleted.

4.2.1 to Deleted.
4.2.8

4.2.9 Scheme has been withdrawn for exports with effect from 1.5.2006. Exports made till 30.4.2006 shall be governed by chapter 4 of FTP (as amended upto 31.3.2007).

DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK (DEPB) SCHEME

Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)	4.3	Objective of DEPB is to neutralise incidence of customs duty on import content of export product. Component of Special Additional Duty and customs duty on fuel shall also be allowed under DEPB (as brand rate) in case of non-availment of CENVAT credit. Neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against export product.
	4.3.1	An exporter may apply for credit, at specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency or payment made from foreign currency account of SEZ unit / SEZ Developer in case of supply by DTA. Credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by DGFT by way of public notice. Credit may be utilized for payment of Customs Duty on freely importable items.
Validity	4.3.2	DEPB holder shall have option to pay additional customs duty in cash as well.
	4.3.3	Validity period of DEPB for import shall be as prescribed in HBP v I.
Transferability	4.3.4	DEPB and / or items imported against it are freely transferable. Transfer of DEPB shall however be for import at specified port, which shall be the port from where exports have been made. Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per terms and conditions of DoR notification.
	4.3.5	Additional customs duty / Excise Duty and Special Additional Duty paid in cash or through debit under DEPB may also be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per DoR rules.
Applicability of Drawback		

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION (DFIA) SCHEME

Scheme	4.4.1	DFIA is issued to allow duty free import of inputs, fuel, oil, energy sources, catalyst which are required for production of export product. DGFT, by means of Public Notice, may exclude any product(s) from purview of DFIA. This scheme is in force from 1 st May, 2006.
Entitlement	4.4.2	Provisions of paragraph 4.1.3 shall be applicable in case of DFIA. However, these Authorisations shall be issued only for products for which Standard Input and Output Norms (SION) have been notified. In case of post export DFIA, a merchant exporter shall be required to mention only name (s) and address(s) of manufacturer(s) of the export product(s). Applicant is required to file application to concerned RA before affecting exports under DFIA. Pre-export Authorisation shall be issued with actual user condition and shall be exempted from payment of basic custom duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any.
Import items	4.4.3	Provisions of paragraphs 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 and 4.1.14 of FTP shall be applicable for DFIA holder.
Value Addition	4.4.4	A minimum 20% value addition shall be required for issuance of such authorisation except for items in gems and jewellery sector for which value addition would be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v1. Items for which higher value addition is prescribed under Advance Authorisation Scheme shall be applicable.
Export Obligation	4.4.5	Procedure and time period related to fulfillment of Export Obligation have been laid down in Chapter 4 of HBP v1.
Transferability	4.4.6	Once export obligation has been fulfilled, request for transferability of Authorisation or inputs imported against it may be made before concerned RA. Once, transferability is endorsed, Authorisation holder may transfer DFIA or duty free inputs, except fuel and any other item(s) notified by DGFT. However, for fuel, import entitlement may be transferred only to companies which have been granted authorisation to market fuel by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Once transferability is endorsed, imports against authorisation or transfer of imported inputs shall be subject to payment of applicable additional customs duty / excise duty. While endorsing transferability, authorisation would bear a note as to liability of

such additional customs duty / excise duty. Such additional customs duty / excise duty would be reimbursed to exporter as drawback. In case of local sales by excisable unit, CENVAT credit would equal excise duty already paid.

Wherever SIONs prescribe actual user condition and in case of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFIA shall be issued with actual user condition for these inputs and no transferability shall be allowed for these inputs even after fulfillment of export obligation.

CENVAT Facility 4.4.7 CENVAT credit facility shall be available for inputs either imported or procured indigenously.

4.4.8 Deleted.

GEMS AND JEWELLERY

Scheme for Gems and Jewellery 4A Exporters of gems and Jewellery can import / procure duty free inputs for manufacturing.

Replenishment Authorisation 4A.1 Exporters may obtain Replenishment (REP) Authorisations from RA in accordance with procedure specified in HBP v1.

4A.1.1 Replenishment authorisation may also be for consumables as per paragraph 4A.28 of HBP v1.

Export of Cut & Polished Diamonds for Certification / Grading 4A.2 Following are authorized laboratories for certification / grading of diamonds of 0.25 carat and above:

- (i) Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat;
- (ii) Gemological Institute of America (GIA), USA;
- (iii) The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) USA;
- (iv) European Gemological Laboratory (EGL), USA;
- (v) Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD);
- (vi) World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium;
- (vii) Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito-Ku, Tokyo, Japan;
- (viii) American Gem Society Laboratories (AGS Laboratories), 8917 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89117;
- (ix) Diamond Trading Company, Maidenhead, U.K; and
- (x) International Diamond Laboratories DMCC, Dubai.

	4A.2.1	An exporter (with turnover of Rs 5 crores annual export for last three years) may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or more) abroad to any of above agencies / laboratories with re-import facility at zero duty within 3 months as per DoR guidelines.
Schemes for Gold / Silver / Platinum Jewellery	4A.3	Exporters of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.
Nominated Agencies	4A.4	Nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation of India Ltd (PEC), Premier Trading House under Paragraph 3.5.2 of FTP and any other agency authorised by RBI. Exporters (except EOU / units in SEZ) may obtain gold / silver / platinum from any nominated agency(s). A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import standard gold bars as per RBI guidelines.
Items of Export	4A.5	Following items, if exported, would be eligible for facilities: (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above; (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight; (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.
Value Addition	4A.6	Value Addition (VA) for gems and jewellery sector shall be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v1. It would be calculated as under:

$$VA = \frac{A - B}{B} \times 100, \quad \text{where}$$

A = FOB value of the export realised / FOR value of supply received.

B = Value of inputs (including domestically procured) such as gold / silver / platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items such as gemstone etc. Wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplier.

Wastage Norms	4A.7	Wastage or manufacturing loss for gold / silver / platinum jewellery shall be admissible as per paragraph 4A.2 of HBP v1.
Export Against Supply by Foreign Buyer	4A.8	<p>Where export orders are placed on nominated agencies / status holder / exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five Crores during preceding three licensing years, foreign buyer may supply in advance and free of charge, gold / silver / platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum for manufacture and export.</p> <p>Such supplies can also be in advance and may involve semi-finished jewellery including findings / mountings / components for repairs / re-make and export subject to minimum value addition of 10%. However, if so imported semi finished gold / silver / platinum jewellery is exported as soddled jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export, wastage of 2% may be permitted.</p> <p>Exports may be made by nominated agencies directly or through their associates or by status holder / exporter. Import and Export of findings shall be on net to net basis.</p>
Export Against Supply by Nominated Agencies	4A.9	Exporter may obtain gold / silver / platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with specified procedure.
Export Against Advance Authorisation	4A.10	<p>An Advance Authorisation may be granted for duty free import of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above; (b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight; (c) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

	4A.11	Such authorisations shall carry an export obligation to be fulfilled as per procedure specified in paragraph 4A of HBP v1. Advance Authorisation holder may obtain gold / silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct import.
Gem Replenishment Authorisation	4A.12	Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Authorisation may be issued as given in paragraphs 4A.8, 4A.9 and 4A.10 above. In case of plain or studded gold / silver / platinum jewellery and articles, value of such Authorisations shall be determined with reference to realisation in excess of prescribed minimum VA. Such Gem REP Authorisations shall be freely transferable.
Gem REP Rate and Item	4A.13	Replenishment Rate and item of import will be as prescribed in Appendix 12B of HBP v1.
Diamond Imprest Authorisation	4A.14	Diamond Imprest Authorisation for import of cut and polished diamonds including semi processed diamonds, half cut diamonds, broken in any form, for mixing with cut and polished diamonds or for export as it is, may be issued for export of cut and polished diamonds and shall carry an EO.
Eligibility	4A.14.1	An exporter of cut & polished diamonds who is status holder may be issued an Authorisation for import of cut & polished diamonds upto 5% of preceding year's export performance of cut & polished diamonds.
Export Obligation (EO)	4A.14.2	EO will be governed by provisions of paragraph 4A of chapter 4 of HBP v1.
Export Promotion Tours / Export of Branded Jewellery	4A.15	Nominated agencies and their associates, with approval of DoC, and others, with approval of Gem & Jewellery EPC (GJEPC), may export gold / silver / platinum jewellery and articles thereof for exhibitions abroad. Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted, subject to conditions as in HBP v1.
Personal Carriage of Export / Import Parcels	4A.16	Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and import parcels by an Indian importer / foreign national may be permitted as in HBP v1.
Export by Post	4A.17	In case of exports through Foreign Post Office (including via Speed Post), value of jewellery parcels shall not exceed US\$50000 and 20 kg. by weight.

Private/ Public Bonded Warehouse 4A.18 Private / Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ / DTA for import and re-export of cut and Polished diamonds, cut & polished coloured gemstones, uncut and unset precious and semi-precious stones, subject to achievement of minimum VA of 5%.

Diamond & Jewellery Dollar Accounts 4A.19 Firms and Companies dealing in purchase / sale of rough or cut and polished diamonds / precious metal jewellery plain, minakari and / or studded with / without diamond and / or other stones with a track record of at least 3 years in import or export of diamonds / coloured gemstones / diamond and coloured gemstones studded jewellery / plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs. 5 crore or above during preceding three licensing years may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts (DDA).

Dollars in such accounts available from bank finance and / or export proceeds shall be used only for

- (i) Import / purchase of rough diamonds from overseas / local sources;
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources;
- (iii) Import / purchase of gold from overseas / nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
- (iv) Transfer to Rupee Account of exporter. Details of this DDA Scheme are given in HBP v1.

A non DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert same into Rupees within 7 days. Cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non DDA holder will also be counted towards discharge of his export obligation and / or entitle him to replenishment Authorisation.

Export of cut & Polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import 4A.20.1 (i) Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export cut and polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import without payment of Customs duty as per customs rules and regulations and subject to condition that exporter shall declare at the time of shipment:

- (a) nature of treatment on cut and polished precious and semi-precious stones; and
- (b) likely change of such stones after treatment.

- (ii) Re-importation would be allowed from the same port from where stones were exported for treatment. On re-importation, customs authority shall cross verify the details with the export documents. A maximum time period of 120 days shall be allowed for re-import.

However in case treated precious stones or semi-precious stones are meant for domestic consumption, re-imported consignment shall be allowed by Customs on payment of duty on fair cost of repairs carried out including cost of materials used in repairs, insurance and freight charges, both ways.

- (iii) Imported items shall be re-exported.

Import of precious metal scrap / used jewellery for melting and re-export of jewellery.

4A.21

Import of precious metal scrap / used jewellery shall be allowed for melting, refining and re-export of jewellery as per the procedure laid down in HBP v1. However, such import shall not be allowed through hand baggage.

Re-import of rejected jewellery

4A.22

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to re-import rejected precious metal jewellery as per para 4A.32 and 4A.32.1 of HBP v1.

Export of Jewellery on consignment basis

4A.23

Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export diamond & jewellery on consignment basis as per HBP v1 and Customs rules and regulations.

CHAPTER-5

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

EPCG Scheme

5.1 EPCG scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD / SKD thereof as well as computer software systems) at 5% Customs duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled in 8 years reckoned from Authorisation issue-date.

In case of agro units, and units in cottage or tiny sector, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods imported in 12 years from Authorisation issue-date.

For SSI units, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods in 8 years from Authorisation issue-date and total investment in plant and machinery after such imports does not exceed SSI limit.

However, in respect of EPCG Authorisations with a duty saved amount of Rs. 100 crores or more, export obligation, shall be fulfilled in 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved provided the same is not Cenvated.

Capital goods shall include spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds.

Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under EPCG scheme.

However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning / operating golf resorts subject to condition that :

- (i) total foreign exchange earning from hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in current and preceding three licensing years is Rs 1.5 crores or m
- (ii) 'duty saved' amount on all EPCG Authorisations issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles / all purpose vehicles shall not exceed 50% of

average foreign exchange earnings from hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in preceding three licensing years.

- (iii) vehicles imported shall be so registered that the vehicle is used for tourist purpose only. A copy of the Registration certificate should be submitted to concerned RA as confirmation of import of vehicle. However, parts of motor cars, sports utility vehicles / all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under EPCG Scheme.

Import of Restricted items of imports mentioned under ITC(HS) shall only be allowed under EPCG Scheme after approval from EFC at Headquarters.

- 5.1A Spares (including refurbished / reconditioned spares), tools, spare refractories and catalyst for existing plant and machinery shall be allowed to be imported subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved to be fulfilled in 8 years reckoned from Authorisation issue-date.

EPCG for Projects

- 5.1B An EPCG Authorisation can also be issued for import of capital goods under Scheme for Project Imports notified by the Central Board of Excise and Customs under S.No 441 of Customs Exemption Notification No 21/2002 dated 01.03.2002.

Export obligation for such EPCG Authorisations would be 8 times of duty saved. Duty saved would be difference between effective duty under aforesaid Customs Notification and concessional duty under the EPCG Scheme.

EPCG for Retail Sector

- 5.1 C To create modern infrastructure in retail sector, concessional duty benefits under EPCG scheme shall be extended for import of capital goods required by retailers having minimum area of 1000 sq meters. Such retailer shall fulfill export obligation i.e., 8 times of duty saved in 8 years.

Eligibility

- 5.2 EPCG scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s) / vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.

Conditions for import of Capital Goods

- 5.3 Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till export obligation is completed.

Export obligation

- 5.4 Following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:-

- (i) Export obligation shall be fulfilled by export of goods,

manufactured / services rendered by the applicant.

Export obligation shall be, over and above, the average level of exports achieved by applicant in preceding three licensing years. Such average would be the arithmetic mean of export performance in last 3 years.

Export obligation may also be fulfilled by exports of group company / managed hotel which has EPCG Authorisation. However, in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above average exports achieved by unit / company / group company / managed hotel in preceding three years, despite exemption in Para 5.7.6 of HBP v1. For this purpose average would be based on previous export of goods and services put together.

- (ii) Shipments under Advance Authorisation, DFRC, DFIA, DEPB or Drawback scheme would also count for fulfillment of EPCG export obligation..
- (iii) Export obligation can also be fulfilled by supply of ITA-1 items to DTA provided realization is in free foreign exchange.
- (iv) Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2 (a), (b), (d), (f), (g) & (j) of FTP shall also be counted towards fulfillment of export obligation alongwith usual benefits available under paragraph 8.3 of FTP.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R&D services shall also be counted for discharge under EPCG. Payment received in rupee terms for port handling services, in terms of Chapter 9 of FTP shall also be counted for export obligation discharge.

- (v) Foreign exchange counted towards fulfillment of export obligation (over and above the average) shall not be eligible for incentives / rewards under promotional measures / schemes.

Provision for BIFR units

- 5.5.1 Any firm /company registered with BIFR or any firm / company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EO extension as per rehabilitation package subject to approval of BIFR or 12 years if not specified.

		Above provisions apply also to SSI units as per rehabilitation scheme of concerned State government.
EPCG for agro units	5.5.2	LUT / Bond or 15% BG (as applicable) may be given for EPCG Authorisation granted to units in Agri Export Zones provided EPCG Authorisation is taken for export of primary agricultural product (s) notified in Appendix 8 or their value added variants.
Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier	5.6	A person holding an EPCG Authorisation may source capital goods from a domestic manufacturer. Such domestic manufacturer shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of FTP. Such domestic sourcing shall also be permitted from EOUs and these supplies shall be counted for purpose of fulfillment of positive NFE by said EOU as provided in Para 6.9 (a) of FTP.
	5.7	Deleted
Fixation of Export Obligation	5.7A	In case of direct imports, export obligation shall be reckoned with reference to actual duty saved amount. In case of domestic sourcing, export obligation shall be reckoned with reference to notional Customs duties saved on FOR value.
	5.8	Deleted
	5.9	Deleted
Technological Upgradation of existing EPCG machinery	5.10	EPCG Authorisation holders can opt for Technological Upgradation of existing capital good imported under EPCG Authorisation
		Conditions governing Technological Upgradation of existing capital goods are as under:
	(i)	Minimum time period for applying for Technological Upgradation of existing capital goods imported under EPCG is 5 years from Authorisation issue-date.
	(ii)	Minimum exports made under old capital goods must be 40% of total export obligation imposed on first EPCG Authorisation.
	(iii)	Export obligation would be refixed such that total export obligation mandated for both capital goods would be sum total of 6 times of duty saved on both the capital goods, to be fulfilled in 8 years from new authorisation issue-date.
	(iv)	Deleted.

- (v) Facility for technological upgradation shall be available only once and the minimum imports to be made shall be at least 10% of the existing investment in plant and machinery by applicant.
- (vi) Capital goods to be imported must be new and technologically superior to earlier CG.

***Incentives for
Fast Track Companies***

- 5.11 To incentivise fast track companies with a view to accelerate exports, in cases where Authorisation holder has fulfilled 75% or more of export obligation (including average level of exports) in half or less than half the original export obligation period specified, remaining export obligation shall be condoned and the Authorisation redeemed by RA concerned.

However no benefits under Para 5.12 of HBP v1 shall be available in such cases.

CHAPTER- 6

**EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE
TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS
(STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)**

Eligibility

- 6.1 Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) Scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re-engineering and rendering of services. Trading units are not covered under these schemes.

**Export and Import of
Goods**

- 6.2 (a) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in ITC(HS).
- Procurement and supply of export promotion material like brochure / literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc. upto a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous years exports shall also be allowed.
- (b) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may import and / or procure from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India without payment of duty all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. Units shall also be permitted to import goods including capital goods required for approved activity, free of cost or on loan / lease from clients. Import of capital goods will be on a self certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.
- (c) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units.
- (d) EOU / EHTP / STP / BTP units may import / procure from DTA without payment of duty certain specified goods for creating a central facility. Software EOU / DTA units may use such facility for export of software.

- (c) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside bonded area.
- (d) Gems and jewellery EOUs may source gold / silver / platinum through nominated agencies on loan / outright purchase basis. Units obtaining gold / silver / platinum from nominated agencies, either on loan basis or outright purchase basis shall export gold / silver / platinum within 90 days from date of release.
- (g) EOU / EHTP / STP / BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit / Escrow Rupee Account of buyer subject to RBI clearance, if any.
- (h) Procurement and export of spares / components upto 1.5% of FOB value of exports may be allowed to same consignee / buyer of export article within the warranty period.

Second Hand Capital Goods

6.3

Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported duty free.

Leasing of Capital Goods

6.4

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may, on the basis of a firm contract between parties, source capital goods from a domestic / foreign leasing company without payment of customs / excise duty. In such a case, EOU / EHTP / STP / BTP unit and domestic / foreign leasing company shall jointly file documents to enable import / procurement of capital goods without payment of duty.

Net Foreign Exchange Earnings (NFE)

6.5

EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner except for sector specific provision of Appendix 14-I-C of Handbook, where a higher value addition shall be required. NFE Earnings shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from commencement of production.

Letter of Permission / Letter of Intent and Legal Undertaking

6.6

- (a) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by Development Commissioner / designated officer to STP/ EOU / EHTP / STP / BTP unit. LoP / LoI shall have an initial validity of 3 years by which time unit should have commenced production. Its validity may be extended further up to 3

years by competent authority. However, proposals for extension beyond six years shall be considered in exceptional circumstances, on a case-to-case basis by BOA. Once unit commences production, LoP / LoI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by DC for a period of 5 years at a time.

- (b) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority subject to compliance of provision in para 6.2 above, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) Unit shall execute a LUT with DC concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render the unit liable to penal action under provisions of the FT (D&R) Act, and Rules and Orders made thereunder without prejudice to action under any other law / rules and cancellation or revocation of LoP / LoI / IL.

Investment Criteria

- (d) Only projects having a minimum investment of Rs.1 Crore in Plant & Machinery shall be considered for establishment as EOUs. This shall, however, not apply to existing units and units in EHTP / STP / BTP, Handicrafts / Agriculture / Floriculture / Aquaculture / Animal Husbandry / Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. Board of Approval (BoA) may also allow establishment of EOUs with a lower investment criteria.

Application & Approvals 6.7

- (a) Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of units in services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by BoA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per criteria indicated in HBP v1.
- (b) In other cases, approval may be granted by BoA set up for this purpose as indicated in HBP v1.
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by Development Commissioner after clearance of proposal by BoA and DIPP within 45 days.

**DTA Sale of Finished
Products / Rejects /
Waste / Scrap / Remnants
and By-products**

6.8

- (a) Entire production of EOU / EHTP / STP / BTP units shall be exported subject to following:

Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports subject to fulfilment of positive NFE on payment of concessional duties. Within entitlement of DTA sale, unit may sell in DTA its products similar to goods which are exported or expected to be exported from units. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, books, tea (except instant tea), pepper & pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time. Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging / labeling / segregation / refrigeration / compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa. Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Exchange Account of SEZ unit. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).

- (b) For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and / or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA subject to fulfillment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in LoP, rejects within an overall limit of 50% may be sold in DTA on payment of duties as applicable to sale under paragraph 6.8(a) on prior intimation to Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap / waste / remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in DTA as per

SION notified under Duty Exemption Scheme on payment of concessional duties as applicable within overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales shall not, however, be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by the norms, DC may, fix ad-hoc norms for a period of six months and within this period, he shall get norms fixed by BoA. Sale of waste / scrap / remnants by units not entitled to DTA sale or sales beyond DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. Scrap / waste / remnants may also be exported.

- (f) There shall be no duties / taxes on scrap / waste / remnants in case same are destroyed with permission of Customs authorities.
- (g) By-products included in LoP may also be sold in DTA subject to achievement of positive NFE on payment of applicable duties within the overall entitlement of paragraph 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales or beyond entitlements of paragraph 6.8 (a) shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU / EHTP / STP / BTP units may sell finished products, except pepper and pepper products and marble which are freely importable under FTP in DTA under intimation to DC against payment of full duties provided they have achieved positive NFE.
- (i) In case of units manufacturing electronics hardware and software, NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) In case of DTA sale of goods manufactured by EOU / EHTP / STP / BTP, where basic duty and CVD is nil, such goods may be considered as non-excisable for payment of duty.
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for first year except pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for first two years.

Other Supplies in DTA 6.9

Following supplies effected from EOU / EHTP / STP / BTP units to DTA will be counted for fulfillment of positive NFE:

- (a) Supplies effected in DTA to holders of Advance Authorisation /Advance Authorisation for annual

requirement / DFIA under duty exemption / remission scheme / EPCG scheme.

- (b) Supplies effected in DTA against foreign exchange remittance received from overseas.
- (c) Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units provided that such goods are permissible for procurement in terms of paragraph 6.2 of FTP.
- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under FTP and / or under section 65 of Customs Act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by MoF.
- (f) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.
- (g) Supplies of Information Technology Agreement (ITA -1) items and notified zero duty telecom / electronic items.
- (h) Supplies of accessories including tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons or hangers to DTA Unit for export.

Export through others

6.10

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured / software developed by it through another exporter or any other EOU / EHTP / STP / SEZ unit subject to conditions mentioned in para 6.19 of HBP v1.

Entitlement for supplies from the DTA

6.11

- (a) Supplies from DTA to EOU / EHTP / STP / BTP units will be regarded as "deemed exports" and DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under chapter 8 of FTP besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. Notwithstanding the above, EOU / EHTP / STP / BTP units shall, on production of a suitable disclaimer from DTA supplier, be eligible for obtaining entitlements specified in chapter 8 of FTP. For claiming deemed export duty drawback, they shall get Brand Rates fixed by Development Commissioner wherever All Industry Rates of Drawback are not available.
- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be

eligible for grant of replenishment authorisations at rates and for items mentioned in HBP v1.

(c) In addition, EOU / EHTP / STP / BTP units shall be entitled to following:-

i) Reimbursement of Central Sales Tax (CST) on goods manufactured in India.

Interest on delay in refund of CST would be paid, as notified.

ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on goods procured from DTA on goods manufactured in India.

iii) Deleted

iv) Reimbursement of Duty paid on fuels procured from domestic oil companies as per Drawback rate notified by DGFT from time to time.

v) CENVAT Credit on service tax paid.

Other Entitlements

6.12

Other entitlements of EOU / EHTP / STP / BTP units are as under:

(a) Exemption from Income Tax as per Section 10A and 10B of Income Tax Act.

(b) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.

(c) Deleted

(d) Export proceeds will be realized within 12 months.

(e) Units will be allowed to retain 100% of its export earning in the EEFC account.

(f) Units will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where unit has

(i) a turnover of Rupees 5 crores or above;

(ii) unit is in existence for at least three years; and

(iii) unit is having an unblemished track record.

(g) 100% FDI investment permitted through Automatic Route similar to SEZ units.

- | | | | |
|----------------------------|------|-----|---|
| Inter Unit Transfer | 6.13 | (a) | Transfer of manufactured goods from one EOU / EHTP / STP / BTP unit to another EOU / EHTP / STP / BTP unit is allowed with prior intimation to concerned Development Commissioner and Customs authorities following procedure of in bond movement of goods. Transfer of manufactured goods shall also be allowed from EOU / EHTP / STP / BTP unit to a SEZ Developer or Unit following procedure prescribed in SEZ Rules, 2006. |
| | | (b) | Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units with prior intimation to concerned Development Commissioner and Customs authorities. |
| | | (c) | Goods supplied by one unit of EOU / EHTP / STP / BTP to another unit shall be treated as imported goods for second unit for payment of duty, on DTA sale by second unit. |
| Sub-Contracting | 6.14 | (a) | <p>(i) EOU / EHTP / STP / BTP units, including gem and jewellery units, may on the basis of annual permission from Customs authorities, subcontract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in DTA.</p> <p>(ii) These units may subcontract upto 50% of overall production of previous year in value terms in DTA with permission of Customs authorities.</p> |
| | | (b) | <p>(i) EOU may, with annual permission from Customs authorities, undertake job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in name of DTA / EOU. For such exports, DTA units will be entitled for refund of duty paid on inputs by way of Brand Rate of duty drawback.</p> <p>(ii) Duty free import of goods for execution of export order placed on EOU by Foreign Supplier on jobwork basis would be allowed subject to condition that no DTA clearance shall be allowed.</p> <p>(iii) Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through other EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP units on the basis of records maintained in unit.</p> |

- (iv) Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with approval of Development Commissioner.
- (c) Scrap / waste / remnants generated through job work may either be cleared from job worker's premises on payment of applicable duty on transaction value or destroyed in presence of Customs / Excise authorities or returned to unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- (d) Sub-contracting / exchange by gems and jewellery EOU through other EOU's or SEZ units or units in DTA shall be as per procedure indicated in HBP v1.
- Sale of Un-utilised Material** 6.15 (a) In case an EOU / EHTP / STP / BTP unit is unable to utilize goods and services, imported or procured from DTA, it may be
- (i) transferred to another EOU / SEZ / EHTP / STP / BTP unit or
- (ii) disposed off in DTA with approval of Customs authorities on payment of applicable duties and submission of import authorisation, or
- (iii) exported. Such transfer from EOU / EHTP / STP / BTP unit to another such unit would be treated as import for receiving unit.
- (b) Capital goods and spares that have become obsolete / surplus, may either be exported, transferred to another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ or disposed of in DTA on payment of applicable duties. Benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA. No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap / waste / remnants / rejects are destroyed within Unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside Unit with permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- (c) In case of textile sector, disposal of left over material / fabrics upto 2% of cif value or quantity of import, whichever is lower, on payment of duty on transaction

value may be allowed, subject to certification of Central Excise / Customs officers that these are leftover items.

- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

**Reconditioning/Repair
and Re-engineering**

6.16

EOU / EHTP / STP / BTP units may be set up with approval of BoA to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 of FTP and para 6.29 of HBP v1 shall not, however, apply to such activities.

**Replacement / Repair of
imported / Indigenous
Goods**

6.17

- (a) General provisions of FTP relating to export / import of replacement / repair of goods would also apply equally to EOU / EHTP / STP / BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by DC.
- (b) Goods sold in DTA and not accepted for any reasons may be brought back for repair / replacement, under intimation to concerned jurisdictional Customs / Excise authorities.
- (c) Goods or parts thereof on being imported / indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, goods may be brought back from foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. However destruction shall not apply to precious and semi precious stones and precious metals.

Exit from EOU Scheme

6.18

- (a) With approval of DC, EOU units may opt out of scheme. Such exit shall be subject to payment of Excise and Customs duties and industrial policy in force.
- (b) If unit has not achieved obligations, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by DoC at price to be determined by that agency.
- (d) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by Development Commissioner, to exit on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme

as a one time option. This will be subject to fulfilment of eligibility criteria under that Scheme and standard conditions indicated in HBP v1.

- (e) Unit proposing to exit out of EOU scheme shall intimate DC and Customs and Central Excise authorities in writing. Unit shall assess duty liability arising out of debonding and submit details of such assessment to customs and Central Excise authorities. Customs and Central Excise authorities shall confirm duty liabilities on priority basis. After payment of duty and clearance of all dues, unit shall obtain "No Dues Certificate" from Customs and Central Excise authorities. On the basis of "No Dues Certificate" so issued by the Customs and Central Excise authorities, unit shall apply to DC for final debonding.

In case there is no proceeding pending under FT(D&R) Act, DC shall issue final debonding order within a period of 7 working days. Between "No Dues Certificate" issued by Customs and Central Excise authorities and final debonding order by DC, unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or input. Unit can however, claim Advance Authorisation / DEPB / Duty Drawback. Since the duty calculations and dues are disputed and take a long time, a BG / Bond / Installment processes backed by BG shall be provided for expediting the exit process.

- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machine procured from abroad after payment of applicable import duty or from domestic market after payment of excise duty and unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after debonding would be without payment of duty. Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under EPCG Scheme and after completely fulfilling export obligation gets converted into EOU, unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA when debonding.
- (g) An EOU / EHTP / STP / BTP Unit may also be permitted by Development Commissioner to exit under Advance Authorization as a one time option. ~~This will be subject to fulfilment of positive NFE criteria.~~

Conversion

6.19

- (a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit, and Income Tax benefits

under Section 10 A and 10 B will be available for plant, machinery and equipment already installed.

- (b) Existing EHTP / STP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will remain in bond and avail exemptions in duties and taxes as applicable.

Monitoring of NFE	6.20	Performance of EOU / EHTP / STP / BTP units shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines in HBP v1.
Export through Exhibitions / Export Promotion Tours / Export through showrooms abroad / Duty Free Shops.	6.21	EOU / EHTP / STP / BTP are permitted to : <ul style="list-style-type: none"> (i) Export goods for holding / participating in exhibitions abroad with permission of DC. (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles. (iii) Export goods for display / sale in permitted shops set up abroad. (iv) Display / sell in permitted shops set up abroad or in show rooms of their distributors / agents. (v) Set up show rooms / retail outlets at International Airports.
Personal Carriage of Import / Export Parcels Including through Foreign bound Passengers	6.22	Import / export through personal carriage of gem and jewellery items may be undertaken as per Customs procedure. Export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import / export through personal carriage by units, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided goods are not in commercial quantity.
Export / Import by Post / Courier	6.23	Goods including free samples, may be exported / imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, as per Customs procedure.
Administration of EOUs / Power of Development Commissioner	6.24	Details of administration of EOUs and power of Development Commissioner are given in HBP v1.
Revival of Sick Units	6.25	Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by BoA.

CHAPTER-9

DEFINITIONS

- 9.1 For purpose of FTP, unless context otherwise requires, following words and expressions shall have the following meanings attached to them.
- 9.2 "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.
- 9.3 "Act" means Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) [FT(D&R) Act].
- 9.4 "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.
- 9.5 "Actual User (Industrial)" means a person who utilises imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.
- 9.6 "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in
- (i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or
 - (ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or
 - (iii) any service industry.
- 9.7 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 8 of HBP v1.
- 9.8 Deleted
- 9.8.1 "Appeal" is an application filed under section 15 of the Act and includes such applications preferred by DGFT officials in government interest against decision by designated adjudicating / appellate authorities.
- 9.9 "Applicant" means person on whose behalf an application is made and shall, wherever context so requires, includes person signing the application.
- 9.9.1 "Authorisation" means a permission as included in Section 2 (g) of FT(D&R) Act to import or export as per provisions of FTP.

- 8.6.2 Supplies made by an Indian sub-contractor of an Indian or foreign main contractor directly to the designated projects / agencies, shall also be eligible for deemed export benefits provided sub-contractor is indicated either originally or subsequently in the contract, and payment certificate is issued by project authority in the name of sub-contractor as in Appendix 22C of HBP v1.

- 8.4.5 In respect of supplies made under paragraph 8.2(e) of FTP, supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable. Benefit of deemed exports shall be available in respect of supplies of capital goods and spares to Fertilizer Plants which are set up or expanded / revamped / retrofitted / modernized during Ninth Plan period. Benefit of deemed exports shall also be available on supplies made to Fertilizers Plants, which have started in the 8th / 9th Plan periods and spilled over to 10th Plan period.
- 8.4.6 Supplies of goods to projects funded by UN agencies covered under para 8.2(i) of FTP are eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable.
- 8.4.7 In respect of supplies made to Nuclear Power Projects under para 8.2(j) of FTP, the supplier would be eligible for benefits given in para 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable. Supply of only those goods required for setting up any Nuclear Power Project specified in list 43 at S.No. 401 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time having a capacity of 440MW or more as certified by an officer not below rank of Joint Secretary to Government of India in Department of Atomic Energy shall be entitled for deemed exports benefits in cases where procedure of competitive bidding (and not ICB) has been followed.
- Eligibility for refund of terminal excise duty / drawback** 8.5 Supply of goods will be eligible for refund of Terminal Excise Duty in terms of para 8.3(c) FTP provided recipient of goods does not avail CENVAT credit / rebate on such goods. Similarly, supplies will be eligible for deemed export drawback in terms of para 8.3(b) of FTP on Central Excise paid on inputs / components, provided CENVAT credit facility / rebate has not been availed by applicant. Such supplies will however be eligible for deemed export drawback on customs duty paid on inputs / components.
- 8.5.1 Interest would be payable on delay in refund of Terminal Excise Duty / Drawback, as notified.
- Supplies to be made by the main / sub-contractor** 8.6.1 In all cases of deemed exports, supplies shall be made directly to designated Projects / Agencies / Units / Advance Authorisation / EPCG Authorisation holders. Sub-contractor may, however, make supplies to main contractor instead of supplying directly to designated projects / agencies. Such Supplies shall be eligible for deemed export benefits as per procedure laid down in paragraph 8.4 of HBP v1.

- 8.4.4 (i) In respect of supplies made under paragraphs 8.2(d), (f) and (g) of FTP, supplier shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c), whichever is applicable.
- (ii) In respect of supplies mentioned in paragraph 8.2(d), supplies to projects funded by such agencies alone, as may be notified by DEA, MoF, shall be eligible for deemed export benefits. A list of such agencies / funds is given in Appendix 13 of HBP v1 .
- (iii) Benefits of deemed exports under para 8.2(f) of FTP shall be applicable in respect of items, import of which is allowed by DoR at zero customs duty subject to fulfillment of conditions specified under Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time.
- (iv) Supply of Capital goods and spares upto 10% of FOR value of capital goods to power projects in terms of paragraph 8.2(g) shall be entitled for deemed export benefits provided the ICB procedures have been followed at Independent Power Producer (IPP) / Engineering and Procurement Contract (EPC) stage. Benefit of deemed exports shall also be available for renovation / modernization of power plants. Supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable. However, supply of goods required for setting up of any mega power projects as specified in S.No. 400 of DoR Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended, shall be eligible for deemed exports benefits as mentioned in paragraph 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable, if such mega power project is :
- (a) an inter state Thermal Power Plant of Capacity of 1000 MW or more; or
- (b) an inter state Hydel Power Plant of capacity of 500 MW or more.
- (v) Supplies under paragraph 8.2(g) of FTP to new refineries being set up during Ninth Plan period and spilled over to Tenth Plan period shall be entitled for deemed export benefits in respect of goods mentioned in list 17 specified in S.No. 228 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time. Supplier shall be eligible for benefits listed in paragraphs 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable.

- (h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers) provided said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs;
- (i) Supply to projects funded by UN agencies; and
- (j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB.

Benefits of deemed exports shall be available under paragraph (d), (e) (f) and (g) only if the supply is made under procedure of ICB.

Benefits for Deemed Exports

8.3

Deemed exports shall be eligible for any / all of following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to terms and conditions as in HBP v1:-

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA.
- (b) Deemed Export Drawback.
- (c) Exemption from terminal excise duty where supplies are made against ICB. In other cases, refund of terminal excise duty will be given.

Benefits to the Supplier

8.4.1

- (i) In respect of supplies made against Advance Authorisation / DFIA in terms of paragraph 8.2(a) of FTP, supplier shall be entitled to Advance Authorisation / DFIA for intermediate supplies.
- (ii) If supplies are made against Advance Release Order (ARO) or back to back Letter of Credit issued against Advance Authorisation / DFIA in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of FTP, suppliers shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(b) and (c) of FTP, wherever is applicable.
- (iii) Deleted.

8.4.2

In respect of supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP in terms of paragraph 8.2(b) of FTP, supplier shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable.

8.4.3

In respect of supplies made under paragraph 8.2(c) of FTP, supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

CHAPTER-8

DEEMED EXPORTS

Deemed Exports

- 8.1 "Deemed Exports" refers to those transactions in which goods supplied do not leave country and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange.

Categories of Supply

- 8.2 Following categories of supply of goods by main / sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under FTP, provided goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFLA;
- (b) Supply of goods to EOUs or STPs or EHTPs or BTPs;
- (c) Supply of capital goods to holders of Authorisations under EPCG Scheme;
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies / funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies / funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;

Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies / funds as notified by DEA, MoF under ICB in accordance with procedures of those agencies / funds, which bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;
- (e) Supply of capital goods, including in unassembled / disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till stage of commercial production and spares to extent of 10% of FOR value to fertilizer plants;
- (f) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the MoF, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty;
- (g) Supply of goods to power projects and refineries not covered in (f) above;

CHAPTER-7**SPECIAL ECONOMIC ZONES**

The policy relating to Special Economic Zones is governed by SEZ Act 2005, and the Rules framed thereunder.

CHAPTER 7A**FREE TRADE & WAREHOUSING ZONES**

The policy relating to Free Trade and Warehousing Zones is governed by SEZ Act 2005, and the Rules framed thereunder.

- Approval for EHTP/STP** 6.26 In case of units under EHTP / STP Schemes, necessary approval / permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by officer designated by Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology instead of Development Commissioner and by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BoA.
- Approval of BTP** 6.27 Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by DGFT on recommendations of Department of Biotechnology. In case of units in BTP, necessary approval / permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of Department of Biotechnology.

- 9.10 "BoA" means the Board of Approval as notified by DoC.
- 9.11 "BTP" means Biotechnology Park as notified by DGFT on recommendation of Department of Biotechnology.
- 9.12 "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. It also includes packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in services sector.
- 9.13 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or Rules and Orders made thereunder or under FTP.
- 9.14 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to another component.
- 9.15 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.
- 9.16 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.
- 9.17 "Counter Trade" means any arrangement under which exports / imports from / to India are balanced either by direct imports / exports from importing / exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports / Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. Balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and / or services.
- 9.18 "Developer" means a person or body of persons, company, firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates,

maintains or manages a part or whole of infrastructure and other facilities in SEZ as approved by Central Government and also includes a co-developer.

- 9.19 "Development Commissioner" means Development Commissioner of SEZ.
- 9.20 "DFRC" means Duty Free Replenishment Certificate.
- 9.21 "Domestic Tariff Area (DTA)" means area within India which is outside SEZs and EOU / EHTP / STP / BTP.
- 9.22 "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported, means rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in manufacture of such goods in India. Goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.
- 9.23 "EHTP" means Electronic Hardware Technology Park.
- 9.24 "EOU" means Export Oriented Unit for which an LOP has been issued by Development Commissioner.
- 9.25 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under Central Excise and Salt Act 1944 (1 of 1944).
- 9.26 "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an IEC number unless otherwise specifically exempted.
- 9.27 "Export Obligation" means obligation to export product or products covered by Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by Regional or competent authority.
- 9.27.1 "FTP" means the Foreign Trade Policy which specifies policy for exports and imports under section 5 of the Act.
- 9.28 "Group Company" means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to
- (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise; or
 - (ii) appoint more than fifty percent, of members of board of directors in the other enterprise.

For group companies to claim benefits or have their exports counted for benefits to be claimed by another member of group, the group company should have been in existence at least 2

years prior to date of application under any of export promotion schemes notified in FTP.

- 9.29 "HBP v1" means the Handbook of Procedures (Vol.1) and "HBP v2" means Handbook of Procedures (Vol.2) published under provisions of paragraph 2.4 of FTP.
- 9.30 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an IEC number unless otherwise specifically exempted.
- 9.31 "Infrastructure facilities" means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for development of SEZ as notified.
- 9.32 "TTC(HS)" means ITC(HS) Classifications of Export and Import Items Book.
- 9.33 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to job worker so as to complete a part of process resulting in manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for aforesaid process.
- 9.34 Deleted
- 9.35 "Licensing Year" means period beginning on the 1st April of a year and ending on 31st March of following year.
- 9.36 "Managed Hotel" means hotels managed by a three star or above hotel / hotel chain under an operating management contract for a duration of at least three years between operating hotel / hotel chain and hotel being managed. Management contract must necessarily cover the entire gamut of operations / management of managed hotel.
- 9.37 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling, Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering. Manufacture, for the purpose of FTP, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.
- 9.38 "Manufacturer Exporter" means a person who exports goods manufactured by him or intends to export such goods.
- 9.39 "MAI" means Market Access Initiative Scheme notified by Department of Commerce.

- 9.40 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.
- 9.40.1 "NC" means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending grant of Authorisations under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by DGFT.
- 9.41 "NFE" means Net Foreign Exchange.
- 9.42 "Notification" means a notification published in Official Gazette.
- 9.43 "Order" means an Order made by Central Government under the Act.
- 9.44 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory.
- 9.45 "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person including the DGFT officials.
- 9.46 "Policy" means FTP 2004-2009 as amended from time to time.
- 9.47 "Prescribed" means prescribed under the Act or the Rules or Orders made thereunder or under FTP.
- 9.48 "Public Notice" means a notice published under provisions of paragraph 2.4 of FTP.
- 9.49 "Raw material" means:
- (i) basic materials which are needed for manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and
 - (ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.
- 9.49.1 "Regional Authority" means authority competent to grant an Authorisation under the Act / Order.
- 9.50 "Registration-Cum-Membership Certificate" (RCMC) means certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council / Commodity Board / Development Authority or other competent authority as prescribed in FTP or HBE v1.

- 9.51 "Rules" means Rules made by Central Government under Section 19 of the Act.
- 9.52 "Services" include all tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.
- 9.53 "Service Provider" means a person providing
- (i) Supply of a 'service' from India to any other country;
 - (ii) Supply of a 'service' from India to service consumer of any other country in India; and
 - (iii) Supply of a 'service' from India through commercial or physical presence in territory of any other country.
 - (iv) Supply of a 'service' in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having being paid for in free foreign exchange by RBI.
- 9.54 "SEZ" means Special Economic Zone notified by Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce.
- 9.55 "Ships" mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade and shall include second hand vessels.
- 9.56 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT in HBP v2, 2004-09 / approved by Board of Approval.
- 9.57 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.
- 9.58 "Specified" means specified by or under provisions of this Policy through Notification / Public Notice.
- 9.59 "Status holder" means an exporter recognized as Export House / Trading House etc. by DGFT / Development Commissioner.
- 9.59.1 "Stores" means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spares and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting.
- 9.60 "STP" means Software Technology Park

- 9.61 "Supporting Manufacturer" means any person who manufactures any product or part / accessories / components of that product. Name of supporting manufacturer as well as the exporter must be endorsed on export documents.
- 9.62 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills shall indicate name of both manufacturing exporter / manufacturer and third party exporter(s). BRC, GR declaration, export order and invoice should be in the name of third party exporter.
- 9.63 "Transaction Value" as defined in Customs Valuation Rules of Department of Revenue.
- 9.64 Deleted
- 9.65 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2(36) of Wildlife (Protection) Act, 1972.